**I.STATUTORY RESOLUTION SEEK ING DISAPPROVAL OF THE VOLUNTARY DISCLOSURE OF INCOME AND WEALTH ORDI NANCE, 1975 (NO. 15 OF 1975) PROMULGATED BY THE PRESI DENT ON THE 8TH OCTOBER, 1975**

**II. THE VOLUNTARY DISCLOSURE OF INCOME AND WEALTH BOX, 1976**

SHRI YOGENDRA SHARMA (Bihar): Sir, I move the following Resolution:

"That this House disapproves the Voluntary Disclosure of Income and Wealth Ordinance, 1975 (No. 15 of 1975) promulgated by the President on the 8th October, 1975."

मान्यवर, यह जो वोलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम लागू की गई है यह पहली बार नहीं बल्कि मेरा ख्याल है इस तरह की चौथी बार स्कीम लागू की गई है ।

[Mr. Deputy Chairman in the Chair].

हम इस स्कीम का निरनुमोदन इसलिये करते हैं कि इस स्कीम के जरिये से टैक्सों की चोरी और काला धन कम होने के बजाय बढ़ेंगे । इस स्कीम के विरोध करने का मूल कारण भी हमारा यही है । सरकार समझती है कि इस स्कीम के जरिये से टैक्सों की चोरी और काला धन दोनों में कमी होगी । यदि कमी होती तो हम सभी के सभी इस बिल का समर्थन करते । लेकिन ठीक इसके विपरीत इस स्कीम का परिणाम हो रहा है और होने वाला है । यदि हम इस स्कीम की विभिन्न बातों को देखें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इससे करों की चोरी और काला धन दोनों हमारे देश में काफी भयंकर स्थिति तक पहुंच गये हैं और मैं समझता हूं कि इसके लागू करने से और भी भयंकर स्थिति में पहुंच जायेंगे ।

पहली चीज जो मैं इस बारे में कहना चाहता हूं वह यह है कि जो टैक्सों की चोरी करने वाले हैं उनको इनाम दिया गया है । इस प्रकार से उनको इनाम दिया गया है और जो ईमानदार करदाता हैं उनको सजा दी गई है । श्रीमन्, इस बात को सभी जानते हैं कि टैक्स कानून के मुताबिक यदि कोई टैक्सों की चोरी करता है तो उसको तरह-तरह की सजायें मिलती हैं और जुर्माने भी होते हैं । कभी-कभी तो इतने अधिक जुर्माने होते हैं कि उसके लिये बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती है । उसको अपने हिसाब-किताब की जांच करवानी होती है और उसके काले कारनामों का पूरे समाज में प्रचार किया जाता है । यही कारण है कि जो ईमानदार टैक्स देने वाले हैं वे ईमानदारी के साथ टैक्स देते हैं । लेकिन आज स्थिति यह है कि जो लोग ईमानदार नहीं हैं, टैक्सों की चोरी करने वाले हैं उनके बारे में इस प्रकार की स्कीम बनाई जा रही है और उन लोगों को इस प्रकार से इनाम दिया जा रहा है । टैक्स की चोरी करने वाले लोग जो भी डिक्लेरेशन करेंगे उसको सामने नहीं लाया जाएगा और उनके हिसाब-किताब की जांच नहीं होगी और उनके बकाये पर सूद भी नहीं लगेगा । उनको किसी प्रकार का जुर्माना भी नहीं देना पड़ेगा । उनका नाम भी नहीं बताया जायेगा । इस प्रकार से ये तमाम चीजें लागू की जा रही हैं । मैं समझता हूं कि इस प्रकार की स्कीम से जो ईमानदार टैक्स दाता हैं उनको धक्का पहुंचेगा और इसका नतीजा इस देश में यह भी हो सकता है कि काला धन और अधिक मात्रा में बढ़ता जाये । ऐसा मालूम पड़ता है कि इस स्कीम के अधीन ईमानदारी से टैक्स देने वालों को सजा दी जा रही है और जो बेईमानी से रुपये कमाते हैं उनको पुरस्कृत किया जा रहा है । हमें इस बात पर आश्चर्य है कि इस स्कीम को किस तरह से लागू किया जा रहा है और इसको एक बिल के रूप में किस तरह से यहां पर पेश किया

जा रहा है। इस स्कीम के सम्बन्ध में इस बात का भी ढोल पीटा जा रहा है कि इसके अन्तर्गत बहुत से डिस्क्लोजर हुये हैं और इस बात के गीत गाये जा रहे हैं कि सरकार के रेवेन्यू में बहुत बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो ढोल पीटे जा रहे हैं और गीत गाये जा रहे हैं, ये वास्तविकता को छिपाने के लिये ही किये जा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि आज हमारे देश के अन्दर जो काला धन है उसके मुकाबले में ये डिसक्लोजर उसके एक पौने के बराबर भी नहीं हैं। हमारे देश के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के मुताबिक इस स्कीम के अन्तर्गत जो साढ़े 14 सौ करोड़ रुपयों के डिस्क्लोजर हुये हैं वे काले धन का मुश्किल से 10 फी सदी भी नहीं हैं। हम इस बिल का समर्थन करते यदि इसके द्वारा अधिक नहीं तो कम से कम 50 परसेंट काले धन का डिस्क्लोजर हो जाता।

SHRI VIREN J. SHAH (Gujarat): Sir, on a point of order. Is there enough quorum here?

SHRIMATI SUMITRA G. KUL-KARNI (Gujarat): Sir, the hon'ble Member is a new Member. Normally in Rajya Sabha quorum is not questioned. This is an unwritten law about our House.

**श्री योगेन्द्र शर्मा** : श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि वास्तविकता यह है कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय आमदनी है उसमें 20 प्रतिशत से भी अधिक काला धन है। आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में 20 हजार करोड़ रुपयों का काला धन है जिसमें सिर्फ साढ़े 14 सौ करोड़ पयों का डिस्क्लोजर हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश में 90 प्रतिशत काला धन अभी भी बना हुआ है और उसका डिस्क्लोजर नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में मैं जानना चाहता हूं कि ये लोग किस बात का ढोल पीट रहे हैं? किस बात का गीत गाया जा रहा है? श्रीमन्, पिछले तीन मर्तबे, जब यह वालण्टरी डिसक्लोज़र स्कीम लागू की गई, और उसके बाद कर विशेषज्ञों ने इस सवाल पर विचार किया, इसके तमाम पहलुओं को छानबीन कर हमारे सामने रखा, तो उन्होंने कहा यह कि इस स्कीम को फिर कभी नहीं लागू करना चाहिए। यह वांचू कमेटी की सिफारिश थी; बहुत मजबूत सिफारिश थी। उन्होंने कहा हम बहुत ही स्ट्रांगली इस चीज़ को रिकमण्ड करते हैं। उसके पहले नेहरू जी के समय में निकोलस कैलंडर बुलाये गये थे उन्होंने इस सवाल पर छानबीन की और छानबीन करके उन्होंने इसी बात को कहा कि इस स्कीम से तमाम काला धन और बढ़ता है, इस स्कीम से कर-वंचना की प्रवृत्ति मजबूत होती है। इतना ही नहीं, श्रीमन्, इस स्कीम के जरिए हमारा जो टैक्स प्रशासन है वह भी पस्त-हिम्मत होता है, उसकी अकुशलता और भी बढ़ती है क्योंकि उनके सामने यदि यह चीज़ आएगी कि भाई, जो आदमी आ कर के तुम को जो भी अपना डिक्लेरेशन दे दे उस को तुम मान लो, उसके बाद वह क्यों माथापच्ची करेगा, क्यों दौड़धूप करेगा टैक्स चोरी का पता लगाने के लिए? तो हमारा टैक्स प्रशासन जो कि बहुत ही कुशल नहीं है टैक्सों को वसूल करने में—हमारा ख्याल है कि टैक्सों के पेमेंट का 50 फी सदी से अधिक बकाया ही रहता है—वह और अधिक पस्त होगा, और यदि टैक्स प्रशासन और भी अधिक पस्त होता है तो कर-वंचना और भी अधिक होती है, यदि कर-वंचना अधिक होती है तो काला धन और भी बढ़ेगा।

श्रीमन्, हमारे देश में जो दण्ड संहिता के आधारभूत सिद्धांत हैं उन आधारभूत सिद्धांतों के खिलाफ यह स्कीम है। हमारे देश

[श्री योगेन्द्र शर्मा]

में दण्ड संहिता का आधारभूत सिद्धांत यह है कि जो अपराध करे उसको सजा मिलनी चाहिए और यदि अपराधी अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है तो उसको कम सजा मिलनी चाहिए। यह है हमारी दण्ड संहिता का आधारभूत सिद्धांत, और यह जो स्कीम है इसमें भी इसके विपरीत सिद्धांत है। वह विपरीत सिद्धांत यह है कि जो टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स चोरी करके काला धन पैदा करते हैं, वह काला धन आज हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को तहस-नहस कर रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाये, उसको पवित्र नागरिक मान कर उसका सम्मान किया जाये तो ऐसी हालत में कर का अपराध बढ़ेगा ही, वह घटेगा कैसे ? क्योंकि आप ने इस देश की दण्ड संहिता के आधारभूत सिद्धांत के ठीक विपरीत काम किया; यह स्कीम उसके विपरीत है।

अब हम सरकार की ओर से जो इस स्कीम के पक्ष में जो दलील दी गई है कुछ उन दलीलों को देखेंगे। पहली दलील तो यह है कि साहब, इसके जरिए से हम को बहुत रेवेन्यू मिल गया--करीब 250 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिल गया है। हमारा ख्याल है यह कुछ बढ़ा-चढ़ा कर कहा गया है। रेवेन्यू उतना सरकार को मिलेगा नहीं। असलियत यह है कि 1450 करोड़ रुपये के डिक्लेरेशन की जो बात है वह भी बढ़ा-चढ़ा कर कही गई है क्योंकि बहुत से डिक्लेरेशन जो हैं वे दोहरे डिक्लेरेशन हैं। एक ही सम्पत्ति को दो-दो आदमियों ने डिक्लेयर किया है और दोनों को जोड़ दिया गया है। तो सही मानों में वह 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं है। और ये डिक्लेरेशन वे हैं जिनकी सूचना हमारे प्रशासन को या तो मिल गई थी या मिलने वाली थी—मिल गई थी जब कि उनके ऊपर छापे मारे गये थे, काग़ज़ात पकड़े गये थे। अधिकतर ऐसे ही डिक्लेरेशन हैं। यदि उस प्रक्रिया को जारी रखा जाता तो हमारा ख्याल है कि 250 करोड़ से ज्यादा रक़म आती।

इस लिए कि साधारण स्थिति में एक लाख रुपये के टैक्स के ऊपर एक ईमानदार कर दाता को 52 हजार 600 रुपया कर के रूप में देना पड़ता है अगर कर प्रशासन ठीक तरह से वसूली करे। लेकिन कर सरकार इस स्कीम के मातहत 46 हजार 250 रुपया वसूल कर रही है और इसके बावजूद भी सरकार कहती है सरकार को 250 करोड़ रुपया प्राप्त होगा और रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी।

सरकार का यह भी कहना है कि इस स्कीम के जरिये नये इंवेस्टमेंट्स होंगे। हम को इस बात की बड़ी खुशी होती कि इस स्कीम के जरिये देश में नये इंवेस्टमट होते, लेकिन हम को खतरा यह है कि नये इंवेस्टमेंट्स नहीं होंगे। इस स्कीम के तहत जो डिक्लेरेशन हुए हैं वे ऐसे डिक्लेरेशन थे जो आलरेडी इंवेस्ट किये हुए थे। मैं यह बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं बल्कि इस सवाल को और इस पहलू को वांचू कमेटी ने देखा और जांच करने के बाद वह एक नतीजे पर पहुंची है जिसको मैं कोट करता हूं :

"As it happens in past cases, the disclosed amounts are already invested surreptitiously in business or property through various devices, and the contribution of disclosure schemes as such to fresh investment is hardly worthwhile."

यह बात वांचू कमेटी की रिपोर्ट में दिया हुआ है और फिर भी सरकार इसके बारे में ढोल पीट रही है कि इसके जरिये फ्रैश इंवेस्टमेंट होंगे। इस स्कीम की जो हकीकत है, वह समाजद्रोही हकीकत है और उस पर आज पर्दा डाला जा रहा है।

दूसरी दलील यह दी जाती है कि इस स्कीम के जरिये ऐसे टैक्स चोर जो पश्चाताप कर रहे हैं अपनी चोरी के लिए, उनको सुधरने का मौका मिल जायेगा। हम इस बात के हक में हैं कि यदि कोई अपराधी अपना अपराध सही मानों में स्वीकार करता है तो समाज को चाहिये कि उसको सुधरने का मौका दिया जाय। लेकिन हम को अफ़सोस है कि इस स्कीम के जरिये से जिन टैक्स चोरों को सुधरने के लिए मौका दिया जा रहा है वे और भी गहरे टैक्स चोर बन जायेंगे और नामी टैक्स चोर बन जायेंगे। ये लोग हैबिचुअल टैक्स इवेडर बन जायेंगे और ज्यादा से ज्यादा टैक्स की चोरी करने लगेंगे। पिछली जो तीन वालिन्टियर डिसक्लोजर स्कीम की गई थीं तो इसके बारे में छानबीन की गई थी और हमारा ख्याल है कि सेन्ट्रल टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बात को स्वीकार किया है कि एक ही तरह के आदमी ने, जिसने पहले वालिन्टियर डिस्क्लोजर स्कीम के मातहत डिसक्लोज किया था, उसने दूसरी बार भी किया और उसी आदमी ने तीसरी बार भी किया। हमारा तो यह ख्याल है कि उसी आदमी ने चौथी बार भी किया है। इस तरह से एक ही आदमी ने पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी वालिन्टियर डिसक्लोजर स्कीम में डिसक्लोज किया है। आजकल जो हमको आंकड़े दिये जाते हैं उसके सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री जी की ओर से कहा जाता है कि हमारे आंकड़े इकट्ठा करने का जो ढंग है वह दूसरे किस्म का है और यही कारण है कि उनके आंकड़े हमारे आंकड़ों के साथ नहीं मिलते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने पिछली तीन स्कीमों में डिक्लेरेशन किया था उनमें से ही बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इस बार की स्कीम में भी डिक्लेरेशन किया है और इस तरह से कैसे वे लोग अपने को सुधार सकते हैं और किस तरह से हम उनको सुधारने में मदद कर सकते हैं? इन लोगों की तो आदत बन गई है और ये लोग इस तरह की कार्यवाही करने और काला धन बनाने के अभ्यस्थ हो गये हैं और हमारी सरकार इस तरह से दस, बारह सालों के आंकड़े बतला कर मुक्त हो जाती है।

श्रीमन्, हमारे कुछ सुझाव हैं। हम सिर्फ़ इस बात को कह कर ही संतोष नहीं कर सकते कि यह जो स्कीम है इससे काला धन घटने के बजाय बढ़ेगा, टैक्स चोरी घटने की बजाय बढ़ेगा। हमारा ख्याल है कि पूरे देश के सामने, पूरे समाज के सामने यह समस्या है कि कैसे काले धन को समाप्त किया जाय, कैसे टैक्स चोरी को खत्म किया जाय। सरकार अब तक जिस रास्ते पर चल रही है और अभी भी इस बिल के जरिये जिस रास्ते पर चल रही है उसका नतीजा हम लोगों के सामने है। यह दोनों बीमारियां बढ़ती ही चली जा रही हैं और कुछ नहीं तो कम से कम इस कारण से तो सरकार को सोचना चाहिए कि कुछ नये उपाय किये जायें और जो दूसरे लोग बता रहे हैं, जो विशेषज्ञ बता रहे हैं उसको भी एक बार मान कर देखा जाय। क्योंकि जब आपके बतलाये हुए तरीके से, आप की नीतियों से काला धन बढ़ता ही जाता है, टैक्स चोरी बढ़ती ही जाती है और आप उसे खत्म करना चाहते हैं—आपकी नीयत में हम को कोई शक नहीं है कि आप इसको खत्म करना चाहते हैं, तो ऐसी हालत में आपको दूसरों के सुझावों पर भी गौर करना चाहिए और उनको स्वीकार करना चाहिए और कम से कम एक बार तो उनकी आजमाइश करनी चाहिए कि आप उनके जरिये भी इस समस्या को हल कर सकते है या नहीं और इस स्पिरिट में मैं कुछ सुझाव सरकार के सामने पेश करूंगा।

पहली चीज तो यह है कि टैक्स चोरों के खिलाफ़ छापामारी को और भी तेज किया

[श्री योगेन्द्र शर्मा]

जाय। हम जानते हैं कि माननीय मंत्री जी कहेंगे कि हम तो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 8 अक्तूबर से यह स्कीम जारी हुई है और 8 अक्तूबर से 31 दिसम्बर के बीच टैक्स चोरों के खिलाफ़ छापेमारी कम हुई है और इससे यह भी शक होता है कि उनके साथ आपकी साठ गांठ है, नहीं तो फ़िर आप ने उन पर छापेमारी क्यों कम कर दी ? तो मेरा पहला सुझाव यह है कि टैक्स चोरों के खिलाफ़ निर्ममता के साथ छापेमारी तेज की जाय। उनका नाम आप बतलायें। हम लोग कहते हैं सरकार से कि उनका नाम बतलाइये, तो सरकार कहती है कि हम ने उनको वचन दिया है, चोरों को वचन दिया है कि हम तुम्हारा नाम नहीं बतलायेंगे। यह जो सामाजिक व्याधि है काले धन की, कर चोरी की, यह सिर्फ़ कानून से ही नहीं सुधरेगी। इसके लिये सामाजिक चेतना बनानी पड़ेगी, इसके लिये आप को पूरे समाज को जाग्रत करना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिये आप को समाज के सामने बतलाना पड़ेगा कि यह यह चोर हैं और आपको बतलाना पड़ेगा कि यह यह साधू हैं। यदि आप उनका नाम नहीं बतलाते, उनका नाम छिपाते हैं, जो डिक्लेरेशन देते हैं उनके डिक्लेरेशन की रकम को छिपाते हैं तो आप समाज को भी सुला देना चाहते हैं और जब समाज सो जायेगा तो फ़िर टैक्स चोरों के पौ बारह हैं। तो इसलिये मेरा सुझाव है कि इन टैक्स चोरों के बारे में अधिक से अधिक पब्लिसिटी होनी चाहिए। पूरे समाज को यह मालूम हो जाना चाहिए कि यह टैक्स चोर हैं और टैक्स चोरों के साथ निर्ममता के साथ व्यवहार होना चाहिए। उनको कोई सामाजिक ओहदा अथवा प्रतिष्ठा नहीं दी जानी चाहिए। सामाजिक निरादर का पात्र उनको होना चाहिए तभी आप इस व्याधि को, रोग को दूर कर सकते हैं।

श्रीमन्, मेरा दूसरा सुझाव है कि टैक्स वसूल करने का जो प्रशासन है उसको और भी सुधारा जाय; और भी मजबूत किया जाय। उसमें सूचना इकट्ठा करने का जो भाग है, जो इंटेलीजेंस विंग है उसको विशेष तौर से मजबूत किया जाय और ऐसा मैं इसलिये कह रहा हूं कि हम देखते हैं कि हमारे देश में जो टैक्स वसूली की हालत है उसमें जो डिमांड होती है उसका करीब-करीब 50 परसेंट एरियर रह जाता है।

1969–70 के आंकड़े हमारे पास हैं जिसमें 786 करोड़ 85 लाख का तो टैक्स इकट्ठा किया गया और 840 करोड़ 70 लाख बकाया रखा गया। मेरा ख्याल है दुनिया के शायद ही किसी देश में एरियर्स का इतना बड़ा परसेन्टेज हो। ऐसी स्थिति में टैक्स प्रशासन को मजबूत करने की आवश्यकता है खासकर इसकी सूचना इकट्ठी करने वाले भाग को अधिक से अधिक मजबूत और प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। उनको एक महीने का बोनस देकर भुलावे में मत डालिये। उनको इस भुलावे में मत डालिये कि तुम आराम से बैठे रहो, टाटा-बिरला आयेंगे खुद डिक्लेरेशन दे जायेंगे। इससे तुम्हारा भी काम हो जायेगा और हमें भी कुछ पैसा मिल जायेगा। हम समझते हैं इससे आपका प्रशासन और भी कमजोर हो जाता है। इसलिये प्रशासन को मजबूत करने के लिये जितने भी आवश्यक कदम हैं उनको उठाइये।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि संविधान की धारा 226 को भी आप संशोधित कीजिये। आप जानते हैं टैक्स चोर बड़े-बड़े लोग हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं और वे लोग टैक्स बचाने के लिये टैक्स महकमे के खिलाफ कोर्ट में चले जाते हैं और 226 धारा के मातहत उनको रिट मिल जाती है। हमारा कहना है कि टैक्स चोरों को रिट नहीं मिलनी चाहिए। यह जो हमारे संविधान की धारा 226 में हाई कोर्ट को अधिकार दिया हुआ है

इसको आप हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन से निकालें। संविधान में आप संशोधन करेंगे तब आपको पता लगेगा कि क्या सही है और क्या गलत।

चौथा मेरा सुझाव यह है कि चेरिटेबुल और रिलीजियस ट्रस्ट जो हैं ये टैक्स चोरी के बहुत बड़े माध्यम हैं, काले धन के बहुत बड़े माध्यम हैं। इसकी जांच पड़ताल करके विशेषज्ञों ने यह सलाह दी थी कि इस संबंध में कानून को मजबूत किया जाये, जिससे टैक्स की चोरी और काले धन का व्यापार न हो सके। हमारा यह कहना है कि आप मेरे इन सुझावों को और खास कर वांचू कमेटी की सिफारिशों को मानें। हमें समझ नहीं आता क्यों आप इस कमेटी की सिफारिशों को नहीं मानते, जिससे कि सही मायने में टैक्स की चोरी पर अंकुश लगता है और काले धन पर भी रोक लगती है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमें आपकी नीयत पर शक होने लगेगा। इसलिये हम मांग करते हैं कि इन सिफारिशों को जो चेरिटेबुल और रिलिजियस ट्रस्ट के मुतल्लिक हैं लागू किया जाये।

MR. DEPUTY CHAIRMAN; Please wind up now.

**श्री योगेन्द्र शर्मा** : आजकल तो बोलने वाले कम हैं, कभी-कभी तो हाउस समय से पहले ही उठ जाता है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We have been allotted two hours. But you have taken more than half-an-hour. Please finish now.

**श्री योगेन्द्र शर्मा** : अभी खत्म करता हूं।

पांचवां सुझाव मेरा यह है कि 100 रुपये और इससे अधिक के नोटों का विमुद्रीकरण करिये। यह भी वांचू कमेटी की एक सिफारिश है और दूसरे लोगों की भी यह सिफारिश है। हम लोग इस बात की बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं पता नहीं इसको मानने में सरकार के हाथ-पांव क्यों फूलने लगते हैं। कर चोरों को रियायत देने में तो सरकार के हाथ-पांव मजबूत हो जाते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का जब सुझाव आता है तो हाथ-पांव फूलने लगते हैं और कहने लगते हैं कि नोट कहां हैं। सब को मालूम है कि अभी 14 सौ करोड़ रुपयों का डिक्लेरेशन हुआ। प्रणव मुखर्जी के मुताबिक करीब सात करोड़ रुपये तो आमदनी के हैं और सात, साढ़े सात के करीब असेसमेन्ट के हैं। इससे पता लगता है कि काफी बड़ी मात्रा में काला धन नोटों में छिपा हुआ है। हम जानते हैं कि इस बिल से काले धन की बीमारी खत्म नहीं होगी, इसलिये हमारी मांग है कि एक सौ और इससे अधिक के नोटों का विमुद्रीकरण करिये।

आखिर में, हम यह भी चाहते हैं कि शहरी सम्पत्ति जो काले धन की हेरा-फेरी का एक बहुत बड़ा साधन है उसकी हदबन्दी की जाये। बहुत दिनों से यह मांग हो रही है और हमारा ख्याल है कि प्रणव मुखर्जी की पार्टी ने भी इस मांग का समर्थन किया है। असल में शहरी सम्पत्ति की सीमा होनी चाहिए, उसकी हदबंदी होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर शहरी सम्पत्ति की हदबंदी कर दी जायेगी तो काले धन की हेरा-फेरी रोकने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने एक राज कमेटी नियुक्त की थी। उस राज कमेटी की दूसरी सिफारिशों के साथ-साथ एक सिफारिश यह भी थी कि कृषि आय पर भी टैक्स लगाया जाय, क्योंकि कृषि के जरिये भी कई लोग धन्ना सेठ बन गये हैं और वे अपना काला धन कृषि में लगाते हैं। इसी काले धन को रोकने के लिए

[श्री योगेन्द्र शर्मा]

राज कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि कृषि आय पर टैक्स लगाया जाय। मैं चाहता हूं कि आप उस कमेटी की सिफारिशों को लागू करें ताकि काले धन का एक बहुत बड़ा स्रोत बन्द हो जाय। ये हमारे सात सुझाव हैं जिनके संबंध में हम जानते हैं कि मंत्री महोदय कुछ न कुछ जवाब दे देंगे। लेकिन आखिर में मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप ने अब तक इस संबंध में जो कदम उठाये हैं उनका परिणाम यह हुआ है कि हमारे देश में काला धन बढ़ता ही गया है और यह काला धन हमारी सारी अर्थ व्यवस्था को ही निगल रहा है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि काले धन के खिलाफ बेरहमी के साथ लड़ाई की जाये। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश से काला धन समाप्त नहीं हो सकता है।

*The question was proposed.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN; Mr. Pranab Mukherjee will now move the Bill.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for voluntary disclosure of income and wealth and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The President promulgated the Voluntary* "disclosure of Income and Wealth Ordinance, 1975, on 8th October, 1975, for providing an opportunity to persons who had evaded tax in the past to declare their undisclosed income and wealth, pay tax thereon on the basis provided in the Ordinance and return to the path of civic responsibility in future. After the scheme of voluntary disclosure had been in operation for some time, it was felt that persons having undisclosed income or wealth in the form of gold and articles or ornaments made of gold would be reluctant to disclose their concealed income or wealth for fear of penal action under the provisions of the Gold (Control) Act, 1968 and the Customs Act, 1962. With a view to removing this and certain other difficulties which may have inhibited persons from making voluntary disclosures, the President promulgated the Voluntary Disclosure of Income and Wealth (Amendment) Ordinance, 1975, on the 29th November, 1975, to make certain modifications in the scheme contained in the Ordinance of 8th October 1975. This Bill seeks to replace the Voluntary Disclosure of Income and Wealth Ordinance, 1975, as amended by the second Ordinance of 29th November, 1975.

Before outlining the main features of the scheme of voluntary disclosure, I propose to briefly indicate the background in which the Government decided to introduce this scheme. As th$_e$ hon. Members are aware, the drive against economic offenders had been stepped up in recent months. The Income-tax Department had taken vigorous action against tax evaders by increasing the tempo of searches and intensifying survey operations through special survey squads. The Taxation Laws (Amendment) Act, 1975, recently passed by Parliament made the punishment for tax offences more stringent. The declaration of emergency concluded with increased pressure on tax evaders. Government took note of the all round awareness of the risk of tax evasion created by these factors and decided to introduce the scheme of voluntary disclosure with a view to providing one last chance to erring tax payers to come to the path of rectitude and civic responsibility.

The scheme of voluntary disclosure which commended on 8th October, 1975, came to an end on 31st December, 1975. The scheme provided for three types of declarations, namely,

voluntary declaration of concealed income; declaration of income in cases of search and seizure; and voluntary declaration of concealed wealth. The voluntarily disclosed income in tJhe first category is treated as a separate block and charged to tax at special rates. In the case of companies, the whole of such income is chargeable to tax at the rate of 60 per cent. In the case of other categories of taxpayers, the first Rs. 25,000 of lhe voluntarily disclosed income is chargeable to tax at the rate of 25 per cent; the income in the slab of Rs. 25,001 to Rs. 50,000 at the rate of 40 per cent; and the balance at the rate of 60 per cent. In addition, the declarant is required to invest 5 per cent of the voluntarily disclosed income in notified Government securities.

The declarant will be immune from any assessment or re-assessment in respect of the voluntarily disclosed income. He will also not be liable to any penalty or prosecution in relation to such income. Besides, the declarant has been exempted from wealth-tax up to and including the assessment year 1975-76 in respect of assets represented by the income disclosed under the scheme.

The scheme has a restricted operation in the case of persons whose books of account, other documents, money, bullion, jewellery etc. have been seized as a result of search by the Income-tax Department. Such persons are not entitled to the benefit of the special rates of income-tax in respect of the income for the year in which the search is made or any earlier year. They could however, make a disclosure in respect of the income for these years and pay tax thereon at the normal rates of income-tax applicable to the total income of the relevant years. The income so declared will not be taken into account for the purposes of levying any penalty or charging interest under the Income tax Act or for the purposes of prosecution under that Act. The assets represented by the concealed income in such cases will be chargeable to wealth-tax in the relevant years, but the value of these assets will not be taken into account for purposes of imposition of penalty or prosecution under the Wealth-tax Act.

.

The scheme also provides for the declaration of undisclosed wealth. The declarant is required to pay wealth-tax in respect of the net wealth or, as the case may be, the value *qt* assets disclosed in the declaration at the normal rates applicable to his net wealth for the relevant assessment year. In addition, the declarant will be required to invest 2J per cent of the disclosed wealth in notified Government securities. The net wealth, or as the case may be, the value of assets so declared, will not be taken into account for the purposes of any penalty or prosecution under the Wealth-tax Act.

Immunity from confiscation, penalty and prosecution under the Gold (Control) Act, 1968 and the Customs Act, 1962 has been provided in the case of persons who declare their concealed income or wealth held in the form of gold or articles and ornaments made of gold. Persons claiming immunity will have to make a declaration in accordance with the provisions of the Gold (Control) Act, 1968 before 1st February, 1976 regarding th$_e$ gold ornaments and articles owned by them. Where the concealed income or wealth is held in the form of primary gold the gold $_w$iU have to be either sold to a licensed dealer or converted into ornaments before that date. Where the gold is held by a declarant in hi$_s$ capacity as a licensed dealer, he will be required to make necessary entries in th$_e$ accounts books, registers and documents maintained by him under the Gold (Control) Act and take such other steps as are necessary for him to comply with the requirements of that Act in relation to such gold before 1st February,

1976. The intention is that whereas

[Shri Pranab Mukherjee] past offences will be condoned, persons making declarations of concealed income and wealth should, hereafter, comply with the requirements of the law, Immunity under these provisions will, however, not extend in relation to gold or articles and ornaments made of gold which are seized by the gold control or customs authorities prior to the declaration or which are the subject matter of pending proceedings before such authorities.

Smugglers and foreign exchange racketeers who have been detained or for whose detention orders have been issued under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 have been specifically barred from the scheme of voluntary disclosure. Further, in order to prevent unscrupulous persons from taking unfair advantage of the scheme by making declarations in the name of *benamindars,* a specific provision has been made that nothing contained in the Bill shall be construed as conferring any benefit, concession or immunity on any person other than the declarant. As the hon. Members are aware, the scheme of voluntary disclosure has proved very successful. According to the latest available information, it appears that 2,45,350 persons made declaration of income amounting to Rs. 744.36 crores. Th$_e$ income-tax payable on the disclosed income works out to Rs. 240.99 crores, of which a sum of Rs. 159.04 crores has already been paid. Concealed wealth has been disclosed in 13,400 cases. The aggregate amount covered by these declarations is Rs. 834.11 crores. The wealth-tax in respect of the disclosed wealth works out to Rs. 7.67 crores, of which a sum of Rs. 4.19 crores has already been paid.

The hon. Members will observe that the scheme of voluntary disclosure has brought out a large amount of concealed income and wealth which can now be channelised into productive fields in the overall interest of the economy. The investment of the disclosed income and wealth into productive activities, instead of on ostentatious consumption, would increase national output and have [a] favourable impact on the price level. In addition to the income-tax and wealth-tax payable on the disclosed income and wealth, a substantial amount has been invested in Government securities which will be utilised by Government for projects of high social priority, like slum clearance and housing for low-income groups. These are substantial gains and justify the Government's decision to introduce the scheme of voluntary disclosure.

In the end, I would like to assure the hon. House that the introduction of the voluntary disclosure scheme does not detract from the Government's resolve to combat tax evasion and other economic offences. In fact, the scheme forms a part of the Government's overall strategy to bring the black money in the main stream of the economy and should be regarded as complementary to the other measures taken in this behalf.

Sir, with" these words, I commend this Bill to the House.

*The question was proposed.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now the Statutory Resolution and the Bill are open for discussion. But, I think, w$_e$ should start the discussion j$_n$ the afternoon. The House stands adjourned till 2.00 P.M.

The House then adjourned for lunch at fifty-eight minutes past twelve of the clock.

The House reassembled after lunch at four minutes past two of the clock.

The Vice-Chairman (Shrimati Purabi Mukhopadhyay) in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): Yes, Mr. Ganguli.

SHRI SALIL KUMAR GANGULI (West Bengal): Madam Vice-Chairman, I rise to speak on the Voluntary Disclosure of Income and Wealth Bill, 1976. This Bill and the previous Ordinance which it is replacing has been a measure of persuasion and coercion. Of course, there has been too much of persuasion and less coercion. According to my Party, too much indulgence has been given to the tax evaders. This tax evasion is now the biggest social evil penetrating its roots into different strata of society and has assumed a very wide dimension. It is sapping the very vitals of the national character We often speak about people not having that much of character which they used to have but one of the reasons why almost everybody has become dishonest or is intending to be dishonest is this taxation structure. Now it has to be admitted in all fairness that a considerable amount of money and wealth has been unearthed and a considerable amount of assets and income which was so far concealed has come into light. It is said that something is better than nothing Some achievement has been made in this sphere. If the money which has been unearthed goes into productive channels, it will improve the economy. But, on the contrary, if it is used again for hoarding and other purposes along with the money which has still not been disclosed, it will play havoc. Therefore, a proper climate should be created so that this money may go into productive channels. This money should be ploughed back into manufacturing units as far as possible and for this purpose the licensing procedures and systems should be reorganised.

The Government should appreciate that the reasons for accumulation of this black money are of their own creation. This black money started accumulating during the war time and particularly it became a terrible phenomenon immediately after the war and attainment of Independence, when the Income-tax Investigation; Tribunal was constituted. Attempts were made at that time to unearth black money which was at that time stated to be around Rs. 400 crores or so. Instead of having schemes of persuasion, at that time, efforts were made to search and to intimidate. In fact, coercive attempts were going on at that time. As a result, the money went underground and generated further black money. If at that time, the Companies Act and other relevant Acts had been amended and suitably re-framed, this kind of phenomenon would not possibly have taken place. However, this tax structure which has been there in this country for the last 25 years or so is becoming more irrational and this does not take into account the inflationary situation. Due to inflation, the value of the rupee has fallen, but the wealth-tax has not been re-structured. Of course, the income-tax exemption limit has been raised. But this is very nominal and it has <not produced any good results. As a result, the income-tax officers, in particular, are overburdened with small cases and small assessees and they have no time to deal with the bigger cases. This requires a lot of re-thinking and the procedure is also very complicated. Justice Sikri of the Supreme Court when he was a sitting judge made the observation which came in tKe papers also that, although he had been dealing with tax cases both as an advocate and as a judge,' he never knew the real intentions and the actual procedures under the Income-tax Act. The system is so complicated.

Now, I think, Government should consider rationalisation of the tax structure as well as upward revision of the exemption limit of income-tax and wealth-tax. In fact, the amount of Rs. one lakh today of wealth-tax exemption, particularly in respect of dwelling houses, has become totally irrelevant due to inflation. The price

LShri Salil Kumar Ganguli]

of land has gone up to such an extent that I do not think that many houses in Delhi can be valued at less than a lakh of rupees. This is not the proper way of doing things. Secondly, the procedure should also be simplified. Even the practising lawyers find it difficult today to fill up the various forms and returns and claiming exemptions and deductions etc. The whole structure and the whole procedure should be simplified and rationalised. A total overhauling of the tax-structure is really needed now. In this connection, I would say that the Government should consider, or have a second look at, the provisions relating to casual gains which in 1972 were brought within the purview of taxable income. Because of these particular provisions, many inventors and authors are now finding it unremunerative to devote their time and energy in the matter of writing books or in inventing things, and even if they do, tlhey want to try to sell surreptitiously the patent rights to the foreigners, and this leads to a great amount of corruption.

With these words, I conclude.

SHRI M. ANANDAM (Andhra Pradesh): Madam Vice-Chairman, the Voluntary Disclosure of Income and Wealth Bill, 1976 replaces the Ordinance issued on the 8th October, 1975. We all know that the various Committees which have gone into the question of black money and tax evasion have suggested a number of measures for checking evasion. The latest Wandioo Committee has also suggested various measures. One of the major things that have been recommended by the Wancboo Committee was that we must tighten up the penal provisions and also have prosecutions so that tax evasion can 1»e avoided. As the hon. Minister has explained in his introductory remarks, before intensifying the prosecutions or the searches and seizures, the Government wanted to give one more opportunity to the people of this country to come forward with disclosures so that if there is any income that has been concealed or any wealth that has been concealed, they can disclose it and start with a very clean slate.

In this context, I welcome the Bill and would say that it is a really a very good measure, giving one more opportunity for the tax-evaders though, of course, I realise that we are placing a premium on the dishonest persons as compared to the honest tax-payers.

Madam Vice-Chairman, this morning the hon. Minister had given us certain figures with regard to the amount disclosed and the number of persons who have disclosed this income, and he has also given the figures with regard to the tax that lh as been collected. He said that nearly 2,45,000 persons have disclosed an income of Rs. 740 crores which has resulted in Rs. 244 crores of tax. Madam, if we work out the average, the tax comes to 30 per cent. And under the Voluntary Disclosure Scheme the minimum rate of tax is 25 per cent on the first. Rs. 25,000 and 40 per cent between Rs. 25,000 and Rs. 50,000. The average works out to 30 per cent; the income that is disclosed is, on an average for each person, Rs. 30,000. I would like to ask the hon. Minister whether he is satisfied that all the black-marketeers who have amassed wealth, lakhs and lakhg year after year, have really and genuinely come forward to disclose all their income and take advantages of this Voluntary Disclosure Scheme. As I said earlier, if each person has disclosed only Rs. 30,000, my analysis of the situation is tlhat this disclosure is made not by the so-called black-marketeers but just by such type of innocent persons who for some reason or other could not file returns but wanted to take advantage of the scheme and start with a clean slate. So, I still say that these black-marketeers who

have been making laklhg and lakhs of rupees and who have made lakhs and lakhs of rupees earlier are still at large and probably the scheme has not been taken advantage of by these [people. This is one thing which I wanted the hon. Minister of Finance to properly investigate and examine and se$_e$ whether he is happy about the situation. We are, of course, happy in the sense that nearly. Rs. 250 crores worth of income has come out in the disclosures but that is not all and this is nothing, that is what I wanted to say.

Then, Madam, there is another thing which I wanted to state with regard to the rates of tax announced under the voluntary disclosure and the difference that is made between a person who disclosed it voluntarily and a person whose houses were raided, whose premises were raided and who has come under searches and seizures. In the case of those whose houses were raided they were allowed to spread over the undisclosed income over a number of years and offer it for tax purposes. This really ha3 come in as a good advantage to those people whose houses were searched. The scheme says that under section 132 (5) of the Act if a search is made that person can get a spread-over of his undisclosed income over a number of years, that is, if say about Rs. 5 laklhs were found in his house, he can spread it over 10 or 15 years and account for a smaller rate of tax under the regular Income-Tax Act 1961 or the Income-Tax Act of 1922. I have known cases where these tax evaders have taken advantage of the •spread-over for more than 10 or 15 years and paid less tax than the other person who has declared it in a lump sum in a particular year. This scheme has come as a disadvantage to other persons who had a marginal income of say Rs. 10,000 or Rs. 15,000 a year. If they had to take advantage of the disclosure scheme and if they have not been filing returns for 10 years, they had to pay income-tax on the income of Rs. 1,50,000 which has come to about nearly Rs. 65,000. Whereas en a regular basis if he had paid the tax on Rs. 15,000 each year, the tax would have come to Rs. 1,000 per year or Rs. 10,000 for all the ten years. So, this scheme has really worked to the disadvantage to those people who really wanted to come forward and make $_a$ disclosure. I know that the hon. Minister may say tihat because they evaded tax they come under the penalty clause. Even the$_n$ it would not come to more than Rs. 20,000 or Rs. 25,000 as against Rs. 65,000 that they were asked to pay under the voluntary disclosure scheme.

The other thing which I wanted to say is with regard to the tempo of searches and seizur$_{es}$ that has been intensified in recent times. I quite appreciate that the Department has been making $_a$ very intensive searches and seizures in almos: all the States. But I want to know in how many of these cases have they been really successful. If I can say from my own knowledge, in the month of December in Andhra Pradesh, in the city of Hyderabad they carried four searches and all the four searches proved abortive. They could not recover anything. They did not got any undisclosed income or undisclosed wealth. Probably most of the searches and seizures are made on the basis of information give$_n$ by certain informers. And we know that these days the$_S$e informers not only try to get some commission out of it, but also they have another purpose behind it, i.e. just to see that the person whose hous$_e$ is searched is humbled. In many cases, the information given by the informers is shoddy. They want to blemish the image of certain persons in the eyea of the public, and that is why they give this informationn. So I suggest that there must be some provision in the Act that if on the basis of the information given by an informer nothing is found, he will be punished.

[Shri M. Anandam]

Then only this type of indiscriminate searches will he avoided. As we have seen from the statistics given by the hon'ble Minister some time ago, in nearly 2,000 searches that have been made, the concealed income is not more tthan 9 to 10 crores of rupees. This is very meagre for the number of searches made.

Another thing I want to say is that even now there are certain people who want to came out and disclose their incomes. I must say that the time of nearly two months given was not at all sufficient for some of the people to come forward and make disclosures. V/'hen we realise that in our country nearly 80 per cent of the population lives in rural areas, the scheme has not reached the villages at all And many of the villagers not only have considerable cash with them but they have also been doing •money-lending business—lending money to the agriculturists. These people were not aware of the implications of the scheme. Therefore, tlhey did not come forward to make any disclosure. I am glad, anyway, that the hon'ble Minister has given an assurance some time ago that even riow such persons can come forward and make disclosures, and he has assured that the Department will take a very lenient view in the matter of levy of penalty and interest. I would suggest that if a disclosure scheme cannot be brought forward now, at least they can say that penal interest will not be charged and that the penalty will be minimum if anybody comes forward with a disclosure. This is necessary because there are a number of persons in villages who would like to come forward and make disclosures of their incomes.

Madam, much emphasis has been placed recently on the rationalisation of the tax-structure. We all know ttiat since 1961 when the present Act was introduced, every year we have been getting amendments in the Act and now the Act has become so complicated that it is not only difficult for the tax-gatherer to accurately interpret it, but it is also very difficult for the tax-cerlifier TO give a proper interpretation of the Act. This is one of the reasons why many people have been defaulters. There is another reason why we should immediately rationalize the entire tax-Structure. While rationalizing we have got to achieve two purposes. One is simplifying the entire law SO" that it is understandable even to the common tax-payer. The second thing is by rationalizing we make the system so easy that nobody tries to evade. That means, we reduce the rates of taxes in such a way that the person trying to pay tax finds it very convenient to do so and he has no desire to evade it. This, I feel, is necessary and should be done immediately.

Madam, there is one way of simplifying the entire law. We know that nearly 50 to 60 per cent of the tax laws come under the penal pro* visions, whether it is in the nature of a penalty or a prosecution. If we have one common law for economic offences, whether it is under the direct taxes or indirect taxes, and we codify all the penal provisions under one law—we can call it the Economic Offences Law—the entire Act becomes very simple and understandable. That I think is a measure which I request the hon. Minister to consider—to tone up the administrative system.

Finally, I want to say that recently the Public Accounts Committee ha3 given a report. About the administration of the Department they have made various recommendations, which are very revealing. They say that the efficiency of the Department is at a very low ebb. If we want that all tax-payers pay their legitimate taxes or the officers collect the legitimate taxes, there & need for training up the entire adrrrin?-

istration. They have also suggested that the internal audit must be strengthened. That means that more officers should be appointed for this purpose. I suggest that the Government must take very serious note of these recommendations and implement them. With these words, I support the Bill.

**श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी** (उत्तर प्रदेश) : उप-सभाध्यक्ष महोदया, मैं आज उस विधेयक के सम्बन्ध में विचार कर रहा हूं जो देश के अन्दर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस समय काला धन हमारे देश के लिए एक बहुत ही चिन्ता का विषय बना हुआ है। और इस देश की आर्थिक समाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सभी ढांचों को लड़खड़ा दिया है। आज हमारे देश में जिन लोगों के मन में समाजवादी भावना के प्रति आदर और सम्मान था, इस काले धन की मार से उनका दिमाग भी समाजवादी योजनाओं को कार्यरूप देने में लड़खड़ा गया है। इस काले धन ने अपना शिकंजा इस प्रकार से कस लिया है कि देश अपनी योजनाओं के अनुसार आगे नहीं बढ़ पा रहा है और जब तक इस चीज से मुक्ति नहीं होगी तब तक देश इस दिशा में प्रगति नहीं कर सकेगा, ऐसी मेरी मान्यता है।

मैं इस सम्बन्ध में कोई मिसाल नहीं देना चाहता हूं लेकिन मैं सरकार का ध्यान एक बात की ओर विशेष तौर पर दिलाना चाहता हूं कि इस काले धन ने हमारे देश के सामाजिक ढांचे को लड़खड़ा दिया है। इस काले धन से हमारे देश में चरित्रहीनता बढ़ती ही चली जा रही है और सरकार इस काले धन से त्रस्त है। आज हमारे देश की स्थिति क्या है, उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस काले धन के सम्बन्ध में बांचू समिति जब विचार कर रही थी तो उसने बतलाया था कि इस तरह का जो काला धन हमारे देश में है, उसकी राशि करीब 7 करोड़ रुपये के बराबर है। उनके एक सदस्य डा० डी० के० रंगनेकर ने बतलाया कि इस देश में करीब 14 हजार करोड़ रुपया काले धन के रूप में विद्यमान है। यह जो रुपया काले धन के रूप में था वह 1968-69 में था। इस समय इस धन की सीमा कहां तक पहुंच गई होगी, इसके बारे में समाचार-पत्रों द्वारा जो बात कही जा रही है कि जिन लोगों ने काले धन के बारे में घोषित किया है उनकी संख्या केवल 10 प्रतिशत ही है। इस समय भी हमारे देश में एक पैरेलल करन्सी चल रही है और जब तक इस तरह की स्थिति देश में चलती रहेगी तब तक हम इस चीज पर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। सरकार की भावना का और सरकार के प्रयासों का मैं समर्थन नहीं करता हूं। सरकार के प्रयास किस रूप में इस सम्बन्ध में है, वह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। जिस तरह से सूखे पेड़ को हरा करने के लिये पेड़ की पत्तियों के ऊपर पानी छिड़का जाता है और जड़ की उपेक्षा की जाती है, उसी तरह के प्रयास सरकार के रहे हैं। जड़ में पानी न डाल कर पेड़ के पत्तों पर पानी छिड़कते हैं। वही प्रयास आप का है और मैं यह कह सकता हूं कि (**व्यवधान**) थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं आप की समझ से बाहर की बात कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप उन को रोकिये। अभी तो इमरजेंसी का नारा लगाया जा रहा है और इधर आप की डिसिप्लिन खत्म होती जा रही है। क्या कर रहे हैं आप ?

**श्री नत्थी सिंह** : चलो, आप ने डिसिप्लिन का सहारा तो लिया।

**श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी** : लेकिन आप इमरजेंसी को तोड़ रहे हैं। आप में सुनने की ताकत भी नहीं है। उपाध्यक्ष

[श्री ओ३म प्रकाश त्यागी]

महोदय, मैं कह रहा था कि जो रुख आप ने अपनाया है उससे तो इस देश में काला धन और बढ़ेगा। मैं अभी साबित करूंगा कि इस से काला धन और कैसे बढ़ेगा। लेकिन जो मार्ग आप ने अपनाया है उस से कालाधन और बढ़ने वाला है। यह पहली बार नहीं हुआ है। यह चौथी बार हुआ है। 1951 में पहली बार इस प्रकार का प्रयास किया गया था। उस समय 70 करोड़ रुपया 81 हजार व्यक्तियों ने डिसक्लोज किया था और उन से आप को 11 करोड़ रुपये मिले थे। उस के बाद 1965 में फिर इसी प्रकार की घोषणा की गयी और उस समय 51 करोड़ रुपया आप को प्राप्त हुआ 12 हजार व्यक्तियों से और 31 करोड़ की आयकर की आमदनी हुई। फिर आप ने 1965 में ही दुबारा घोषणा की और फिर 145 करोड़ की आमदनी हुई दस हजार व्यक्तियों से और जब 1975 में आप ने फिर घोषणा की है। यह आप ने चौथी बार किया है। आप इस प्रकार का लगातार एक्सपेरीमेंट कर रहे है। पहली बार होता तो में समझ सकता था। मैं जानना चाहता हूं कि हर दस साल बाद क्या इस प्रकार काले धन वालों के लिये, जो काला बाजार कर रहे हैं, जो देश के शत्रु हैं, जो देश के ढांचे को लड़खड़ा रहे हैं उनको इस प्रकार की छूट देते रहेंगे ? यह आप ने चौथी बार किया है और क्या आप इस को फिर दस साल बाद दोहरायेंगे ? ऐसा क्यों हो रहा है ? मैं कहना चाहता हूं कि यह जो प्रयास है इस से आप का काला धन और बढ़ेगा और यह मेरी राय ही नहीं है। यह बांचू कमेटी की राय है। उस की रिपोर्ट में इस प्रकार लिखा है :

"A voluntary disclosure scheme is an extraordinary measurement for abnormal situations such as after a war or at times of national crisis. Resorting to such a measure during normal times and that too frequently, would only shake the confidence of the honest tax-payer in the capacity of the Government to deal with the law-breakers and would invite contempt for its enforcement machinery. Any more disclosure scheme would not only fail to achieve the intended purpose of unearthing black money but would have a deleterious effect on the level of confidence among the tax-paying public and on the morale of the administration. The idea of introduction of any general scheme of disclosure either now or in future is, therefore, strongly opposed.'

यह बांचू साहब की राय है। इस प्रकार जो आप बार बार छूट दे रहे हैं इस से बढ़ावा मिलेगा काले धन को और जो टैक्स पेयर लोग हैं उन लोगों के हौसले पस्त हो जायेंगे। ऐसी उन की राय है। मैं समझता हूं कि उस राय का आप को आदर करना चाहिए अन्यथा यह काला धन और बढ़ेगा। मैं समझता हूं कि यह सरकार काले धन पर नियंत्रण नहीं कर सकी है और मैं समझता हूं कि सरकार की नीतियों का दिवालियापन है। यही एक शब्द इस संबंध में कहा जा सकता है। आप काले धन को पैदा होने से नहीं रोक सके और आप का बार बार कहना कि दे दो, इस बार माफ किया, इस बार माफ किया, यह क्या है ? आप काले धन को पैदा होने से रोक क्यों नहीं सके ? ऐसा न कर पाने में ही आप की नीतियों का दिवालियापन प्रकट होता है, आप की इस प्रकार की घोषणाओं से आप का दिवालियापन प्रकट होता है ?

**अध्यक्ष महोदय**, सरकार को इसमें कितनी सफलता मिली है यह मैं बताना चाहता हूं। सरकार की सफलता मिली है केवल 10 परसैन्ट। कहना यह है कि 10 परसैन्ट का सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में दो-तीन मिसालें

देना चाहता हूं । मुखर्जी साहब आपने जो घोषणा की वह खतरनाक साबित हुई है। मुझे मालूम नही आपको जानकारी है या नहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं बम्बई गया था तो एक जगह पर बड़ा रश था और वहां पर कुछ लोग हंस रहे थे । मैंने पूछा, भाई क्या बात हैं। कहने लगे कि कमाल हो गया है । काले धन को रोकने के लिये गवर्नमैन्ट ने स्कीम निकाली है लेकिन आज तो काला धन आकाश को चूम रहा है और लोगों ने इस स्कीम का बड़ा लाभ उठाया है। मैंने पूछा ऐसी क्या बात हो गई है तो उन्होंने कहा कि घोषणा यह हुई है कि जो डिक्लेरेशन करेगा किसी अचल सम्पत्ति की या किसी और चीज की तो उसकी प्रेजैन्ट बैल्यू नहीं मानी जाएगी, पुरानी वैल्यू ही मानी जाएगी । मान लीजिये इस वक्त जो मेरे पास सम्पत्ति है वह दो करोड़ की हैं जब कि उसकी पुरानी वैल्यू दो लाख की हैं। आपने इस प्रकार हमारी सम्पत्ति को दो लाख की स्वीकृति दी है पुराने वैल्यू के हिसाब से । इसके मायने यह हुए कि 91.8, करोड़ पया बिल्कुल छूट में चला गया । यहां तक कि प्रेजेन्ट वैल्यू का 10–20 गुणा चला गया हैं । आपको मालूम है आज की और पुरानी चीजों की कीमतों में आकाश पाताल का अन्तर है । इसी कारण लोगों ने धड़ाधड़ डिक्लेरेशन दे दी । इसका परिणाम यह हुआ कि काला धन और बड़ी तादाद में बना लिया गया प्रेजैन्ट वैल्यू के आधार पर । इसलिये मेरा आपसे कहना है कि आप इसकी जांच कराइये कि ऐसा हुआ है या नहीं ।

दूसरी चीज जो आपके यहां हुई वह यह है कि आपके यहां जो टैक्स कमिशनर है उन्होंने भी डिक्लेरेशन करने वालों से सांठगांठ की हुई थी । हो सकता है आपका प्रैशर पड़ा हो कि डैक्लेरेशन नहीं हो रहा है वह कराया जाए। मैं बताना चाहता हूं कि काला धन सबसे ज्यादा लगा हुआ है बिल्डिंग बनाने में । मैं समझता हूं आपने रेड भी डाली है बड़े बड़े शहरों में । जिन्होंने मकान बनाए हैं या जिन्होंने अपार्टमैन्ट खरीदे हैं उनके साथ आपके टैक्स कमिशनर ने सांठगांठ की । उनसे कहा गया कि आप अपने मकान की डिक्लेरेशन कीजिये, घोषणा कीजिये । यह भी कहा गया कि आप को 85 टू 90 परसैन्ट अनएकाउंटेड व्यय के आधार पर छूट दे दी जाएगी और बाकी हिसाब पर आप से टैक्स ले लिया जाएगा । मुखर्जी साहब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार का डिक्लेरेशन जो हुआ है मकानों के संबंध में या अपार्टमेंन्ट के संबंध में, उसमें से कितना टैक्सेबल अमाउंट था और कितना पूरा अमाउंट और उसमें से आपने कितनी छूट दी है। उस पर कितना टैक्स लगाया । इस प्रकार के आंकड़े अगर आप दे सकें तो आपकी बड़ी कृपा होगी ।

अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसा मैंने शुरु में कहा कि आप काले धन को इस बिल से रोक नहीं सकेंगे । आपको देखना है कि इस काले धन की जड़ कहां है । और उस पर विचार करना है । मैंने पीछे लोकसभा में भी कहा था लेकिन गवर्नमैन्ट अपने ही मार्ग पर चले जा रही है । कारण जहां तक मैं समझ पाया हूं यह है कि जो ब्लैक मनी या अपार धन राशि जिसके पास है उन्होंने आपको ऐसे शिकजे में बांधा हुआ है कि आप जो भी नीति बनाते हैं, स्कीम बनाते हैं वह लड़खड़ा जाती है और आप उनके खिलाफ एक्शन भी नहीं ले पाते ।

आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं और हमारे देश का कानून भी ऐसा नहीं है जिसमें इस प्रकार की सख्त कार्यवाही हो सके । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि हम देश के अन्दर चल रहे टैक्स इवेजन को रोकें । हमारे देश के

[श्री ओइम् प्रकाश त्यागी]

अन्दर जो काले धन का निर्माण होता है उसको बन्द किया जाय । इसलिए श्री मुखर्जी को सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि आपका जो टैक्स विभाग है उसके जो कानून और नियम हैं उनमें आप संशोधन कीजिये, उनमें सुधार कीजिये । अभी तो हमारे देश में स्थिति यह है कि वर्तमान कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सौ रुपये कमाता है तो उसको 97 रु० गवर्नमेन्ट को देने पड़ते हैं और केवल मात्र 3 रु० उसके पास रह जाते हैं । ऐसी स्थिति में आप स्वयं इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि जब किसी बिजनेस मैन को सौ रुपयों में 97 रु० सरकार को देने पड़ेंगे तो वह किस तरह से अपनी आमदनी का डिसक्लोजर करेगा । अगर आपका कानून ऐसा भी होता कि किसी बिजनैस मैन के पास सौ रुपयों में से 50 रु० तो रहेंगे ही तो बात कुछ समझ में आ सकती थी । इसका परिणाम यह भी होता कि हमारे देश का बहुत सा धन देश के उत्पादन कार्यों में लगता । कहा जाता है कि आज हमारे देश में 25-30 हजार करोड़ रुपयों की ब्लैक मनी चल रही है । अगर हमारे देश का टैक्स संबन्धी कानून तर्कपूर्ण और ठीक होता तो इतनी बड़ी रकम हमारे देश में रचनात्मक कामों में लगती और हमारे देश का उत्पादन भी बढ़ता । उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ देश में वस्तुओं के मूल्यों में भी गिरावट आती । लेकिन आजकल हमारे देश में जो टैक्स लेने का ढंग है वह लोगों को टैक्सों की चोरी करने के लिए प्रोत्साहन देता है । अगर कोई बिजनेस मैन इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट के पास अपना खाता लेकर जाता है तो आमतौर पर वहां के कर्मचारी उससे कहते हैं कि तुम्हारी आमदनी इतनी नहीं है और तुम यह गलत हिसाब दे रहे हो । अगर कोई आदमी अपना सही हिसाब लेकर जाता है और कहता है कि मेरी 2 लाख की आमदनी है तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि तुम्हारी दो लाख की आमदनी नहीं है, तुम्हारी 10 लाख की आमदनी है । ऐसी हालत में कौन ईमानदार बिजनैस मैन होगा जो अपना सही हिसाब लेकर इनके पास जाएगा । हमारे देश के टैक्स के कानून इस प्रकार के हैं जो लोगों को टैक्स की चोरी करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं और यही कारण है कि हमारे देश में प्रत्येक बिजनैस मैन दो प्रकार के खाते रखते हैं । एक खाता तो उसका अपने घर का खाता होता है और दूसरा खाता वे इनकम टैक्स विभाग को दिखाने के लिए बनाते हैं जिसमें वे यह बात दर्शाते हैं कि अगर उसकी आमदनी 20 लाख रुपये है तो इनकम टैक्स विभाग को 5 लाख रुपये ही दिखाये जाते हैं । सरकार की इनकम टैक्स की गलत नीति के ही कारण आज हमारे देश में दो प्रकार के खाते चल रहे हैं । इसलिए मेरा कहना यह है कि इन डबल खातों को बन्द करने के लिए आप अपने इनकम टैक्स कानूनों और नियमों में परिवर्तन कीजिये । हमारे शास्त्रों के अन्दर भी कहा गया है कि टैक्स उसी प्रकार लेने चाहिए जिस प्रकार से मधुमक्खी अर्थात् भौरा फूलों से रस ग्रहण कर लेता है और फूलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है; उसी प्रकार से सरकार को भी टैक्स लेने चाहिए जिससे टैक्स देने वाले को किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचे । इसलिये मेरा कहना यह है कि आप टैक्स के ढांचे को रिजनेबल बनाइये ताकि टैक्स पेयर को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो और वह यह समझे कि टैक्स देने में उसको लाभ है ।

दूसरी बात अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग टैक्सों की चोरी करते हैं या टैक्स इवेडर करते हैं उनको इतनी

कड़ी सजा दी जानी चाहिए कि वे टैक्सों की चोरी न कर सकें। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से जो टैक्सों की चोरी करते हैं वे देश के प्रति गद्दारी करते हैं, इसलिए उनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। इस संबन्ध में मैं आपको एक मिसाल देकर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। कुछ दिन पहले मुझे ईस्ट अफ्रीका जाने का मौका मिला। तंजानिया के प्रेजीडेन्ट श्री न्यरेरे ने मुझे कहा कि—

"Mr. Tyagi, your Indians are trying to corrupt my officers. I will not tolerate that."

उन्होंने मुझे कहा था उस टाइम कि भारतवर्ष के लोग, हमारे देश के लोग भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। उन्होंने भारतीयों को चेतावनी दी थी। 5-6 महीने बाद उन्होंने नियम बनाये और इस प्रकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो नियम बनाये और एक आदमी पकड़ा गया। एक महीने बाद वह जेल से छूटकर आया। मैं उससे मिलने गया और जब मैं गया घर पर, तो, वह उल्टे पड़े थे। यों, मैंने कहा हाल क्या हैं। मैंने देखा वे पीठ उघाड़े हैं। क्या हुआ? सजा मिली महीने भर की वह इतनी सख्त नही थी पर सजा जो दूसरी मिली, जेल आने पर शुरू में 14 कोड़े लगे और जेल से छुटने पर 14 कोड़े लगे। कोड़े और हंटर लगने से उसकी पीठ छिली हुई थी ताकि दूसरे लोग अपराध करने से बच सकें। अगर इस तरह के आप कड़ें कानून बनायेंगे तो इस देश में काले धन को रोक सकेंगे अन्यथा जो घोषणायें आप करते हैं यह तो एक भले आदमी को भी चोरबाजारी करने के लिये प्रोत्साहन देती है। वे समझते हैं कि दस साल के बाद छूट मिलेगी तो फिर दस साल तक बिगाड़ क्या है। अफसोस की बात है कि मुखर्जी साहब अपना स्टेटमेंट देते रहेंगे कि इतना डिसक्लोजर हो गया है और इससे टैक्स इवेजन में कुछ कमी आ जायगी। लेकिन ऐसा करके आप काला धन पैदा होना रोक नहीं सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक की भावना का तो स्वागत करता हूं परन्तु सरकार के इस प्रयास का कड़ा विरोध करता हूं।

SHRIMATI SUMITRA G. KUL-KARNI (Gujarat): Madam, Vice-Chairman, please let me take this opportunity to congratulate our Minister for this Voluntary Disclosure Scheme which has now been presented to this House as a Bill. Madam, I am a little surprised that all the Members *on* the Opposition side have been deriding it. 1 personally think that in the past attempts were made, but at least now, for once, we have succeeded, and We havg succeeded in breaching the parallel economy that was going on in thig country. After all, we must recognize the efforts put in by the Government. Whether we like it or not, it was a successful effort to a great degree. And if this is a successful effort, at least there is hope and that in future there will be more successful efforts. So, here is a question of appreciating the intentions of the Government. The results are also quite commensurate with our expectations.

Madam, at least Rs. 1500 crores of wealth has been flushed out, and we will be getting about Rs. 300 crores by way of taxes on this, including wealth-tax and income-tax. Now, Madam, of course, this has shown one thing: Thig country has got a vast amount of black money available. One can easly say that about Rs. 1500 crores black money $j_s$ still flowing round in the country. This has assured the Government that there is such a thing available. This particular Bill will encourage the Government to take further steps in the right direction.

[Shrimati Sumitra G. Kulkarni] Another very good point which occurs to me is that, Madam, once this •wealth has been declared and it has been put as white money, it can never go back into black money. This means that for years to come we will be get-tiig recurring wealth-tax on this mc aey; this is not a gain only for this yenr but this is a perpetual gain in the years to come also.

Another small point also, which is in favour of this scheme, is a side benefit which we have received, and I am sure the hon. Minister has noticed it. For the information of the House, Madam, as well as for your information, I may say that for the last year and a half, so many raids were conducted, so much material and so many books of accounts were seized, and all these were piled in the Income-tax offices, and they were not being cleared. We just did not have any other machinery to handle it. Thanks to this Voluntary Disclosure Scheme, at one stroke this blacklog of work in the offices has been cleared and the headaches of the Income-tax Department and the Ministry of Finance are considerably reduced.

Similarly, Madam, under the Income-tax Act there are the Acquisition of Property Rules. Under this head also, innumerable cases were pending in courts for the last more than 10 years. They were becoming a nightmare. They have also been cleared at one stroke. This is the achievement part of this thing. These are minor achievements, but they have far-reaching results. In this connection, I would like to sincerely commend the work that has been done by the Ministry of Finance and the Government.

However, Madam, there is never any Bill which can be a perfect Bill. After all, it is a human effort and there are bound to be weaknesses. I would like to urge upon the Minister that when I do point out the weaknesses, the intention is not to deride in the least. It is only to examine ourselves and to find out what are the possible loopholes that have been left out and what We can do to make up for these things which are bound to be left out in the first attempt. Madam, the first thing that occurs to me and which other Members here have also mentioned, is that an honest assessee feels like a fool. When he was honest two years ago, he was paying 97.7 per cent of income-tax. Since last year, he is paying 77.7 per cent of income-tax. Now, today under this Voluntary Disclosure Scheme, a man gets away with merely 60 per cent. If only he had been dishonest, he would have straight way saved 39.7 per cent. He feels cheated that his honesty has not been recognised. In fact, this Voluntary Disclosure Scheme puts a premium, if I may say so on dishonesty and a premium on default. I am sure the Government do not want such a thing and they would like to rectify this situation also.

There is another small thing. Under this Scheme, a man who has not filed the current year's return, can also disclose. Now, an honest person who has filed the return for the current year will be paying income-tax at 77.7 per cent, but the man who has taken advantage of this Voluntary Disclosure Scheme will be paying at the rate of 60 per cent. This is an anomaly. For the very same year, one man will be paying 77.7 per cent and the other person who wants to cheat and do underhand things will be paying 60 per cent. This aspect will have to be borne in mind and we should try to improve upon this weakness of this particular Bill.

There is another thing which our distinguished friend, Mr. Anandam, also brought out. He, of course, brought out the point very well that only 30 per cent of the persons have disclosed. If we look into all the disclosures, I am afraid that there will be benami disclosures or even

fictitious disclosures under the name of A, B or C. In this way, maximum benefit is availed of with the minimum disclosures. Their method is to get back this money by way of loan or by some other method. The real persons who are the real sharks of this business, are not netted. They are getting away by using this scheme in the name of minors, fictitious servants or other persons. This should also be looked into.

Madam, there is another thing which occurs to m'e. It is that by our systematic attempts during the last 4 or 5 months, we have helped the lower income group by rising the lower exemption limit of income-tax from Rs. 6,000 to Rs. 8,000. Very good. It was very essential and it should be there. We have also helped the high income group by bringing down the rate of income-tax from 97.7 per cent to 77.7 per cent. Over and above this, now comes this Voluntary Disclosure Scheme and we have been forced to reduce it to 60 per Cent. But what about the salaried classes and middle-class people? They are not getting any benefit. The bulk of the income-tax comes from the middle-class group people. They are feeling let down. They are not getting the kindly hand and the more considerate aspect of the Government's attitude. As there is a salaried class and a professional class, there is another class where the logic acts differently. And that is, there are innumerable persons in the villages, belonging to the middle-class, who are not paying any income-tax This real middle-class is not paying income-tax because it is a tremendous temptation and incentive to evade taxes under the present tax structure. Now, this is what is fTap-pening. These are some of the things which we have to take care. The salaried class [a]lso should get some benefit, and the middle-class which is escaping the net of income-tax should also be brought into it.

Madam, against these weakness of this Bill, I would like to submit a few suggestions. These are my humble suggestions but may be administratively quite effective in the present circumstances, and I would recommend them for the kind consideration of the hon. Minister. Madam, the real remedy for cutting down the evasion and the default is to reduce the rate of taxation. Already, under this scheme, we have reduced it to 60 per cent. At least, in future, the percentage should never be more than 60. If we achieve this thing, I think, We would be really gaining much more than what we are getting today. Madam, today the benefits have been given to the top sector and to the bottom sector but the middle sector is left out. So, my suggestion is that the benefits should be equally spread over to the entire income-tax-paying sector by cutting down ten per cent tax rate from each slab. The top slab has already got reduction by 37 per cent. But the rest also should be given ten per cent reduction. But, of course, we will be losing revenue. My point is that the loss of ten per cent will be set off very much by gaining on the cut-down of evasion, and many people will be less tempted to evade and commit defaults, and thereby the chances are that our recovery will be much more than our loss of ten per cent of revenue by reducing this tax rate. Madam, as you know, after the Second World War, Japan reduced the taxes by half. They just slashed the taxes by 50 per cent and within five years, the revenue return was doubled up. I do not say that you do it. But the Government should hear this thing in mind that if it is within reasonable limits, people will be more interested in being honest and there will be a premium on honesty instead of a premium on dishonesty as *h* happening today. Now, I will just illustrate a small point which is not really relevant under the present circumstances because we" no longer have 97.7 per cent taxation.

[Shrimati Sumitra G. Kulkarni]

But about two years ago, Madam, Rs. 2,300 of black money was equal to Jls. 1 lakh of white money. Naturally, the temptation was tremendously great that it was so easy to evade taxes on Rs. 2,300 while it was much more difficult to put in the effort to earn Rs. 1 lakh. Under those circumstances, even the most honest person, the law-abiding person, was forced and felt like giving up his cultural tenets and taking to this new method. They felt, may be, dishonesty will pay us, at least, will satisfy our urge for initiative and entrepreneur-,ship. But, Madam, this is only a part ,of the monetary loss. But the thing which is much worse than this monetary loss and which worries me is that the intellectual integrity which was suffering. The best talent in this .country, the highly intelligent people, the best financial brains and highly talented people were engaged in financial jugglery, in manipulating the business and in hood-winking the Government instead of being engaged in increasing the productivity of this country. Just imagine if this talent was available for some creative work, for productive work, and for increasing the industrial production of the country, what would have been the gain? So it is essential that we do give them scope for working because these talented people have adopted this kind of anti-social attitude which was reflecting on the entire society and was affecting the moral code of this country. Now at least we have taken a reasonable step and that should reduce the temptation for these persons and they will divert their energy for better productivity in the country. Therefore, it is essential that we think on th$_e$ lines of curbing our taxation.

The second suggestion is about the lowest exemption limit which is Rs. 8000 today. Madam, under the present circumstances, this Rs. 8,000 is not really much of an income. My humble suggestion would be that it should b$_e$ raised to Rs. 12,000. I remember that the hon. Finance Minister had said that the loss of revenue will be so great that we cannot afford it. When the present exemption limit of Rs. 8,000 was announced, at that time also we were there and I had argued about it and I was told that the loss would be so much that we could not afford it. Madam, I have tried to calculate it and it works out to somewhere between Rs. 15 crores and Rs. 20 crores. Even if it comes to Rs. 30 crores, it is really not such a big loss, it will rather boost up the morale of the lower classes. Much more than that, our Income-tax Department is over burdened, working on petty cases of income-tax asses-sees. They have to waste their time on such petty cases, sending summons, preparing papers and all that. Even the administrative machinery to handle these cases would cost more than Rs. 30 crores and I feel that we would be saving $_s$o much by increasing this exemption limit. So it is not at all disadvantageous. The Ministry of Finance should raise this limit to Rs. 10,000 and we will still be gaining rather than suffering any loss.

My third point is that we have now generated a tempo in our country by raids, seizures and other measures but this tempo cannot be continued for a long time in its present intensity. This work is so stupendous and so wide that no one machinery can handle it. We are not equipped with that kind of machinery today to handle this kind of a situation. I feel that we may select some special industrial sectors, just a small segment of the industry, may be textiles, or sugar industry or cotton and 'jute industry and our machinery should concentrate on that only. The entire effort of the Government should be to examine only that particular industrial sector. They may leav« free all

the rest. Let the Income-tax Department and the Ministry of Finance have all the opportunity of carrying it out properly and thoroughly. They can impose a deterrent punishment, if necessary.

Another suggestion that I have to make is, under section 143(1) of Income-tax Act, Madam, we should take all the income-tax returns which are filed, at their face value. We should not waste time scrutinising them and haggling with them and arguing with them, and we should ask the people to pay tax according to the returns filed by them. Under this scheme, automatically collection of taxes will be made. It will relieve the departmental officers of the drudgery of going through the returns. The Department could take up ten per cent of these cases, where such returns have been filed, and examine them in absolute detail and do a thorough job of it and take them to logical conclusions. By this system, not only will the department be able to examine those cases thoroughly but it will also give sufficient time to the Department to concentrate on more and more important cases of disclosures. So this is the system which should be tried because, Madam, I feel that it is much better and much more effective to examine ten P$^{er}$ cent of the cases thoroughly rather than go on ineffectively tinkering with each individual case without much success. It is much better that we concentrate on ten per cent of the cases.

Lastly, I would like to suggest that we should strengthen the in come-tax machinery. We want that the entire black money in this coun try should be unearthed so that the parallel economy is eradicated. I do not say that it will be eradicated completely, but it can be curbed to ; a greater extent. For this, it is essen tial that the department and the income-tax-collecting machinery should be strengthened. This is the premier revenue-earning agency in our country. But unfortunately,—I am sure the House will agree with me—we treat this service most shabbily. Most of the people in the country look at the income-tax officers with suspicion. If we want that they should do their work with honesty, integrity and enthusiasm in their hearts for the benefit of the country, it is essential that we should recognise their merit. It is good that the hon. Minister has given them one month extra salary. This is a token gift. What we should really do is to make their working conditions better and improve their promotional prospects so that they may feel encouraged to work better. If , we want to recognise their services to the country, the least that we can do is to place the income-tax service on par with the India$_n$ Administrative Service. Why should the Indian Administrative Service have superiority over the revenue-earning service? Today, a young junior Income-tax Officer Clas$_s$ II takes vital decisions and decides cases worth lakhs and lakhs of rupees without any help. If he can exercise this kind of ingenuity at this young age on a little salary, certainly this country and this Government should have the magnanimity to recognise this and place the service on par with other services, if not higher. If we do this, I am sure every income-tax officer in this country will hold his head high and will do his best for the country. We want that the entire black money in this country should be unearthed so that this can be made use for accelerating the industrial growth, for eradication of poverty and for implementing the twenty-point programme. For all these purposes, it is necessary that we should instil a sense of confidence in th$_e$ mind$_s$ of the income-tax officers and place the service on par with the Indian Administrative Service.

[The Vice-Chairman (Shri V. B. Raja) in the Chair]

SHRI DHARAMCHAND JAIN (Bihar): Sir, I thank the hon. Minister and the Government for this timely measure. No doubt, it has fetched Rs. 1500 crores and about Rs. 250 crores by way of tax. But at the same time, there was a great rush on the last day and I think the Ministry of Finance should have extended the time at least by a fortnight.

Now, why is this black money generated? First of all, black money is a wrong name; it should be 'unaccounted money'. Why is this unaccounted money generated? First of all, the rate of taxation is so high and there is no incentive for honesty. Therefore, conditions have to be created so that people may become honest and incentives should be offered to them to pay the taxes honestly. I would appeal to the Minister that when he presents the Budget, he should consider reducing the tax limit to around 50 per cent. Strong measures can be taken if there is tax evasion even then. As it stands today, the Income-tax Act, after various amendments every year, has become very complicated. Even for the lawyers and the assessees it is difficult to keep track of them and I think even the officers of the departments sometimes get lost with these amendments. I request you to look into this and possibly have a new Act in 1976.

The Administrative cost in the Finance Ministry should also be reduced. In the Income Tax Department, paper work by the assessees and the ITOs is too much. You have to introduce some system whereby a return is accepted. You have to accept the returns as filed and in some stray cases you can make inquiries and complete the assessment, if necessary. Under the present system, a man has to run at least ten to fifteen times if not more. So, this sort of wastage of time on both sides can be avoided and the officers can give you better results if you introduce some new system.

You have said in the statement that there have been about 2,000 raids and seizure of about Rs. 17 crores. But the amount of tax you are going to get out of that is not known to any of us. It should also be made clear as to what would be the revenue out of those seizures and whether conducting the raids, the amount spent on them and the exercises done were really worth or not.

As you know, now there is a great demand for building industries in various areas and also for starting industries in the backward areas. As it is asid that the unaccounted money is still in circulation. I want to know whether it will be worth while for you to consider allowing, up to a certain period of time, investment of such unaccounted money in the industrial sector, without asking them from where the money came.

With these words, Sir, I support the Bill.

SHRI B. RACHAIAH (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Bill that has been brought forward by the Minister. The Bill seeks to replace the Ordinance of the 8th October, 1975 and as amended on the 21st November, 1975.

Sir, many hon. Members have given their views on this Bill. Our efforts for getting the undisclosed wealth and income tax disclosed, have not proved effective in earlier years according to the figures furnished by the Minister. I must congratulate the Minister for the timely and correct decision in recommending to the President to issue such an Ordinance. Now the conditions are created in such a way that to those people who did not disclose their wealth or income, there is no other go except to disclose them. If the department had

not taken vigorous steps by searches and raids, I think it would not have given them any deterrent to disclose their wealth. Even though the measures taken by the department in searching have not given sufficient money, they cautioned, and acted as a deterrent to, those who had not disclosed them. Such a situation was created and another condition also was created by giving them some incentives under taxes and some immunity from confiscations penalty and prosecution under the Gold Control Act and Customs Act 1968.

The first variety is of those people who disclose their incomes now volun. tarily. They will be given a certain concession rate of interest on the tax that will be payable by them. Except in the case of raids and seizures, the declarants will have certain benefits between 40 to 60 per cent tax concession and they will not be penalised for having not disclosed earlier. This is really an encouragement and a good condition to those people to come forward to disclose their wealth. The people who have declared their wealth earlier and those who have given their assets correctly, they should be given certain further relief for being honest. That was the argument made by some of th$_e$ hon'ble Members. I agree with them that they also need some encouragement. Sir, according to the reports available, the black money is still having an overriding influence over our economy. We have not been able to unearth all the parallel money that is there in the country. Therefore, we have not been able to bring down the prices to the extent we wanted and we have to see that the honest people, honest officers, are encouraged. Therefore, Sir, I was pointing; out that the undisclosed wealth is still there. It requires further consideration whether we should give some more time to see that the undisclosed wealth comes out. Therefore, our attempts in respect of searches and raids should continue relentlessly on the one hand. And on the other we must give some more time to those people who have not been able to avail of this" opportunity and concession to disclose their wealth. Sir, while speaking on the motion of thanks on the President's Address, I fervently appealed to the Government that some more time, if given, will not be in vain. It will really be a gain to the Exchequer in terms of getting more concealed wealth for assessment in future. Up till now income and wealth of about Rs. 1500 crores has been disclosed, out of which Rs. 250 to Rs. 300 crores by war of taxes will be coming to the Ex chequer year after year.

Sir, Mr. Jain has also made a proposal that those people who are having all this parallel money or black money or tax evaded money, they should be allowed to invest it in an investment which will increase production in the country—be it in our industrial development, or be it in the form of agricultural development. Sir, I looked through the reports of some of these committees and nowhere in the world so much of tax evasion is there in India. And, Sir, rightly last year and the year before we gave some relief to the assessees. We must create a condition in the country that the honest way of living alone is helpful to them and gives them an honourable place in society. Therefore, the people will realize that the Government is honest, the officers involved are honest, and the dishonest way of dealing with things will never help them. Officers should not only be efficient but also be honest. Their integrity should be above board. This occasion may be utilised to *reed out dishonest officials in th$_e$ Administration.

I am not saying for a moment that all the officers who are there in the Income-tax Department are honest or dishonest. There may be a few black sheep. But there are good officers also. What have you done for them? If they have found out any income or conduct any raid, have you

[Shri B. Rachaiah]

given them any incentive by way of advance promotion or by way of recognising them on important days like the Republic Day or on other important national holidays? You have not given them any such encouragement. In the police department police medals are given to them for the meritorious service that they have rendered. But in this department you have not encouraged them to be more honest, to use their skill and ability to their utmost. I was hearing Mr. Anandam when he suggested that some of the raids have been conducted only on the information received by the department, and some proved to be futile and no income or wealth was found out. Undisclosed money was also not found. In such cases what prevents the department in publishing that such and such a house was raided and that nothing was found. That will really give relief to the person whose house has been raided. This is for the consideration of the Minister because it will give him the lost prestige or status in the society.

I was thinking whether it is not possible for the Ministry to reorganise its statistical division for colecting correct data and the materials required for the future rationalising of the law that the Ministry is contemplating. Unless this is done, whatever laws we are making here, we will be making them only on the assumption and in the absence of correct figures. Therefore, such a cell is necessary in the Ministry so that we get correct information and we are able to assess really what is the law that is required for rationalising the tax structure.

With these words, I support the Bill that has been brought forward by the hon. Minister. I congratulate him once again for the earnest efforts that he has taken in getting for the exchequer so much money and for creating a condition in the country that those people who have declared their wealth will not be punished afterwards and to have brought them to the path of rectitude and responsibility.

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस अध्यादेश द्वारा जो असर देश में हुआ उससे पुरानी याद आती है, जब सरदार पटेल ने बड़े-बड़े रजवाड़ों को, जो कहते थे कि हम ने रियासत अपनी शक्ति से जीती है, हमारे बजुर्गों ने हथियारों के दम पर इसको बनाये रखा है, हम भविष्य में भी इसको इसी तरह से कायम रखेंगे। जो रजवाड़े इस तरह की बात कहा करते थे वे सब चन्द दिनों के बाद चलते बने और सरदार पटेल की सख्त कार्यवाही की वजह से आज इस देश में एक भी न रियासत है और न कोई रजवाड़ा ही है।

हमारे कुछ भाई, विरोधी दल के सदस्य समझते थे कि उनके साथ बहुत रियायत हो रही है, वह रियायत भी जाती देखी और उनके वजीफे भी खत्म होते देखे। इसी तरह से आर्थिक क्षेत्र के अन्दर भारत सरकार ने जो यह तजुर्बा किया है, उसकी कामयाबी की यह पहली कड़ी है कि उसने 1550 करोड़ रुपये या जायदाद का पता लगा लिया। इस तरह का जो उसने असर किया है वह कोई छोटा काम नहीं है। यह काम खास तौर पर ऐसे मुहकमे के मारफत किया गया जिसके बारे में श्री धर्म चन्द जी का कहना है कि वहां पर कोई भी ईमानदार नहीं है। अगर उस मुहकमे से कोई फैसला लेना हो तो उसके लिए साल, दो साल, तीन साल, चार साल लगते और दस, पन्द्रह चक्कर करने पड़ते हैं। कई दफा तो यहां तक नौबत पहुंचती है कि जितना टैक्स देना होता है उससे ज्यादा तो वकीलों को देना पड़ जाता है और फिर भी केस का फैसला नहीं होता। इस तरह से वहां पर फाइलों में और

कागज में लटपट रहता है और इस तरह से कोई चीज या कागज वहां से बड़ी मुश्किलों से निकल पाता है। इस तरह का जो महकमा है उसने इस कानून के जरिये 1550 करोड़ रुपये या रुपयों की जायदाद निकाल दी, यह कोई छोटी बात नहीं है। और इतनी जायदाद का पता करने या काले धन का पता करने के लिये सरकार का कितना पैसा खर्च होता इसका हिसाब लगाया जाय तो समझ में आ सकता है कि इस बिल का कितना फायदा हुआ है। तो जहां मैं इस बिल का समर्थन करता हूं उसके साथ-साथ मैं यह भी कहे बगैर नहीं रह सकता कि इस देश के अंदर हम दो किस्म का समाजवाद लाना चाहते हैं। एक समाजवाद उनके लिये कि जो देहातों में बसते हैं, या जो गांवों में रहेंगे उनके लिये और दूसरा जो तनख्वाहदार है, जो शहरों में रहते हैं, जो कारखाने चलाते हैं उनके लिये। मैं जानना चाहता हूं कि समाजवाद का यह तौर तरीका आखिर कब तक चलेगा। आज तो ऐसी बात नहीं है कि गांवों के अंदर, देहात के लोगों को मत का अधिकार न हो। इस देश में कुल 15 या 20 ऐसे हल्के हो सकते हैं कि जिनमें तनख्वाहदार या कारखानेदार ही मत के अधिकारी हों, वरना बाकी 540 हल्कों में से ज्यादातर में तो देहात के लोग ही बसते हैं। तो एक तरफ अभी बहिन सुमित्रा जी ने कहा और बड़ी काबलियत के साथ कहा कि जो कम से कम आपकी आठ हजार की सीमा है इन्कम टैक्स को लगाने के लिए उसको बढ़ा कर दस हजार कर दिया जाय।

**श्रीमती सुमित्रा जी० कुलकर्णी** : 12 हजार के लिये कहा।

**श्री रणवीर सिंह** : ठीक है, आठ हजार से बढ़ा कर 12 हजार कर दी जाय और 12 हजार बचाने का अधिकार पति को हो और 12 हजार का अधिकार पत्नी को हो, तो हर साल 24 हजार की आमदनी टैक्स से मुक्त रहे और यहां 12 एकड़ रखने का अधिकार है। 12 एकड़ की सीलिंग है। पहले ही 16 हजार कर मुक्त हैं अब आप उसको बढ़ा कर 24 हजार तक ले जाना चाहते हैं। तो कौन से समाजवाद का नक्शा हम को आप दिखाना चाहते हैं यह सोचने वाली बात है। यही नहीं, आप देखें कि जैसा उन्होंने कहा उसका मुकाबला हम दूसरे टैक्सेज से करें तो कितना खर्चा आता है। छोटे छोटे केसेज में टैक्स वसूल करने के लिये उसका हिसाब लगायें तो आपको पता चलेगा। लैंड रेवेन्यू जमीन हैका कर। आज तो जमीन सरकार की जायदाद नहीं रही, वह तो लोगों की जायदाद है। भूमिकर को किराया तो आप नहीं कह सकते। और फिर उस जमीन की आमदनी कैसी है। वह किसी कारखानेदार की तरह किसी ठंडे या गर्म कमरे में बैठ कर हासिल नहीं की जा सकती। वह तो खून और पसीना बहा कर सर्दी और गर्मी में मेहनत करके हासिल की जाती है। तो एक तरफ उनके लिये आप की सीलिंग है और दूसरी तरफ आप का 12 हजार का सुझाव है। तो यह दोनों बातें तो समता की भावना के विपरीत हो जाती हैं। कुछ भाइयों का ख्याल है कि जो यह आपात् कालीन स्थिति है, या इसे त्याग की स्थिति कहें या उसे कानून मानने वालों का युग कहें या अनुशासन युग कहें जैसा कि विनोबा जी ने कहा, यह युग हिन्दुस्तान के लिये कितने फायदे का साबित हुआ है वह इस बात से ही साबित होता है। इसके अलावा समझदार से समझदार जिनके पास वकील थे, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिये पैसे थे, वे सब हाथ जोड़ बैठे। वकील को भी इस पर गिला है। सभाध्यक्ष जी, जो वैल्थ टैक्स इस साल लगेगा वह आज की कीमत पर लगेगा और इससे छिपी हुई जायदाद सामने आयेगी। आपने देखा, छिपी हुई जायदाद सामने आई भी है। जो जायदाद सामने आई है उसका दुबारा री-वैल्युएशन होगा।

[श्री रणबीर सिंह]

सभाध्यक्ष जी, हमारे आर्थिक विज्ञान के जानने वाले वित्त मंत्रालय की नीतियों को देखिए। पहले जो कार की कीमत थी उससे कहीं डेढ़ गुना आज बढ़ गई है इसलिये कार बिकती नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि कार तो आराम की चीज है उसके दाम तो बढ़े ही हैं परन्तु जो पैदावार के लिये ट्रैक्टर होते हैं, इनकी भी कीमत इन्हीं पांच-सात सालों में चौगुनी हो गई है। अगर वह पांच साल पहले 10 हजार का था तो अब उसकी कीमत 40 हजार हो गई है। अगर वह 20 हजार का था तो उसकी कीमत एक लाख हो गई है। यह आर्थिक अन्याय वित्त मंत्रालय कब तक चला सकेगा यह हमारी समझ में नहीं आता। वित्त मंत्रालय को इस पर बड़ी गम्भीरता से सोचना चाहिये। जो नारे बाजी चल रही है कि जमीन के अंदर आमदनी बहुत है तो मैं पूछना चाहता हूं जमीन के अंदर आमदनी है कहां। सरकार को कीमती से कीमती यह बात भी देखनी होगी कि सरकार के जो फार्म हैं, जिनमें सरकार की मशीनरी लगी हुई है, सरकार के करोड़ों रुपये लगे हुए हैं वे घाटे में क्यों जाते हैं। यह सामान्य बात है कि बगैर पैसे के, बगैर सामान के और बगैर जरिये के किसान ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता। फिर उसे उन पैसों में से अपने बच्चों को तालीम भी देनी है, मकान भी बनाना है। अगर ऐसी हालत में उस पर टैक्स लगता है तो यह घाटे के ऊपर टैक्स है।

**डा० रामकृपाल सिंह**: भूपेश जी को सुनाइए।

**श्री रणबीर सिंह**: डा० साहब, यह तो आपके सुनने की बात है भूपेश जी की पार्टी तो कह ही चुकी है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री वी० वी० राजू)**: चौधरी साहब आगे कहिये।

**श्री रणबीर सिंह**: जैसा आपने इशारा किया मैं इनकी तरफ न जाकर आगे अपनी बात कहता हूं। यह ठीक है कि आज पैसे की जरूरत है। अपनी योजनाओं को चलाने के लिये, देश की तरक्की के लिये पैसा चाहिये। हमारी आर्थिक सोच यह है कि अगर नहर बने और उसके ऊपर पैसा लगाये तो उसका ब्याज प्रदेश सरकारें दें और अगर गांवों में बिजली दी जाय तो स्टैट इलेक्टरीसिटी बोर्ड उस रुपये पर ब्याज दे और दूसरी तरफ अगर लोहे के कारखाने लगें तो जितनी शेयर कैपिटल है उनके ऊपर ब्याज नहीं लगे। अगर वह कर्ज लेंगे तो उसके ऊपर ब्याज लगेगा। हमारा कहना यह है कि नहरों को और देहातों में बिजली के अदारों को कब तक प्राइवेट जायदाद मानते रहेंगे और कब आपकी सोच बदलेगी।

एक्साइज ड्यूटी की भी बात आई है। आज मैं आप से पूछना चाहता हूं कि ट्रैक्टर की जो आज कीमत है उस पर कितनी एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है। ट्रैक्टर एक ऐसी चीज है जो पैदावार बढ़ाने के लिये है इसलिये इस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाये उस पर अच्छी तरह से सोच-विचार करके लगाई जाये।

यह भी कहा जाता है कि काला धन इसलिये इकट्ठा होता है क्योंकि 97 परसेन्ट टैक्स लगता है। मैं कहना चाहता हूं कि उन पर 97 परसेन्ट टैक्स लगता है जो बड़े-बड़े कारखानेदार हैं। वहां पर एक्साइज ड्यूटी के इंस्पैक्टर्स और स्टेट पुलिस बैठी रहती है क्योंकि वहां से काला धन निकल नहीं सकता है। तो उसमें काला धन बनता है और काला धन तभी बनता है जब कारखानेदार गलत ढंग से व्यापार करते हैं और सामान को अपने रिश्तेदारों के पास रखते हैं।

मैं इस बात को मानता हूं कि हिन्दुस्तान में काला धन पैदा होने के कई तरीके हैं। लेकिन सरकार ने इस संबंध में जो नीति बदली है उसके परिणामस्वरूप काफी काला धन बाहर आया है और लोगों ने अपनी सम्पत्ति के आंकड़े दिये हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में जो अर्थ शास्त्री हैं और जो किताबें पढ़कर टैक्स लगाने की बात करते हैं वे ठंडे और गरम कमरों में बैठ कर विचार करते हैं। उनको गांवों की वास्तविकताओं का पता नहीं होता है। आज जो यह बात कही जाती है कि गांवों के अन्दर किसानों की आमदनी बढ़ गई है, इसलिए उन पर टैक्स लगा दिया जाय, यह वास्तव में सही स्थिति नहीं है। मान लीजिये किसी के पास 5 एकड़ जमीन है तो आप इस बात का अन्दाजा किस प्रकार लगाएंगे कि उसकी आमदनी कितनी है। जमीन पर कभी तो अच्छी फसल हो जाती है और कभी नुकसान भी हो जाता है। मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्रालय के जानकारों को गांवों की स्थिति का ज्ञान नहीं है। मैं यह भी समझता हूं कि हमारे इनकम टैक्स वालों को भी गांवों की स्थिति की जानकारी नहीं है। एक एकड़ जमीन में कितना टोटा होता है और कितना फायदा होता है, इसका अनुमान वे नहीं लगा सकते हैं।

**उपसभाध्यक्ष (श्री वी० वी० राजू)** : ये बातें तो आप जनरल बजट पर बहस के वक्त कह सकते हैं।

**श्री रणबीर सिंह** : इसलिए अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपातकालीन स्थिति के अन्दर इस प्रकार की जो स्कीम बनाई गई है, उसके लिए मैं मंत्री महोदय को और मंत्रालय को बधाई देता हूं और साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि देहात वालों के साथ जो सौतेली मां जैसा व्यवहार किया जाता है, जब तक आप इस सौतेले व्यवहार की नीति को नहीं बदलेंगे तब तक हिन्दुस्तान का आर्थिक ढांचा सही तौर पर काम नहीं कर सकेगा। आपको गांवों के किसानों और मजदूरों के साथ न्याय करना होगा।

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF THE DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am grateful to the honourable Members for supporting the provisions of the Bill. Even Mr. Yogendra Sharma, while moving his Resolution for disapproving the Ordinance, has, by and large, supported the various measures taken by the Government to fight black money and to plug the loopholes through which black money is being generated and operated.

Sir, while making my introductory remarks, I also made it clear that the Scheme of Voluntary Disclosure of Income and Wealth is not an isolated measure and it should not be treated out of context. For quite some time we have been taking measures to fight black money and searches and seizures and various other measures have been intensified as a result of which it was found necessary, and it was thought advisable, to introduce a scheme like this which might provide an opportunity to the tax dodgers to come forward and make their accounts clean and to resort to the path of civic rectitude. There is no denying the fact that it can be seen from the figures which I have quoted that, by and large, they have responded to this. But, Sir, at the same time, it has to be kept in mind that in a country like ours the taxation policy is not just an economic exercise, but it is something which has manifold objectives and it is a complex one and the problems cannot be sorted out or solved merely by one or two measures like this. I would not like to enter into the controversy about the quantum of black money, whether it is Rs. 7000 crores or Rs. 14,000 crores, as has been suggested by some Members, quoting some reports from here and there. If we accept the basis fact that quite a

[Shri Pranab Mukherjee]

substantial quantum of black money has been generated during the last few years ai.;l it is distorting our economic activities to a considerable extent, even from that premise we shall have to come to the conclusion that a sizeable amount of income and wealth have come and that will contribute to tho mainstream of the economy.

While making his observations, Mr. Sharma indicated that when the Scheme was in operation, we reduced the number of raids. Sir, it is not correct. And, if I may be permitted to say so, I can tell that there was even intensification of raids during that period. I would not like to mention any particular name here. But even some of the very big houses were subjected to raids and searches which created an atmosphere m which the Voluntary Disclosure Scheme was successful to some extent. And if we look at the figures of the number of raids, searches and seizures conducted by the Income-tax Department during the last 9 months, from April 1975 to 31st December 1975, we shall find that the total number of raids was 2061. Sir, the total number of raids during this period in the last year was 1615. Therefore, the number of raids has increased. As I have mentioned in the other House, this is a continuing effort. We have taken certain measures by amending the Income-tax laws as per the recommendations of the Wanchoo Committee, by intensifying searches *i-\d* raids and by enhancing the

•*iwers of the Incometax Department.

'ot only that, we have done ihat en by enhancing penalties and link-

ig up the quantum of punishment

with the amount of tax evasion. We xiave taken these measures, and this is a continuing exercise.

But, at the same time, as I was pointing out, Sir, it has to be kept in mind that in a situation in which we are living, we cannot keep our eyes shut to the realities. I would like to give juat one information to hon. Members. When, last year, $w_e$ conducted a survey, as a result of which quite a large number of new assessees were brought within the tax net, quite a large number of them, out of 2 lakhs, belonged to liberal professions such as Law, Engineering, Medicine, Accountancy, etc. I have nothing to speak against any particular profession or against any individual. But it is an indicator that eeven the cream of the socety ,even the elites of the society, resort to tax evasion or tax avoidance. Therefore, merely by strengthening the administrative machinery or merely by plugging the loopnoles here and there, the problem of tne generation of black money, tax evasion and avoidance cannot be tackled altogether. I do, therefore, entirely agree with Mr. Yogendra Sharma that a strong public opinion has to be created in the society where the society as such would disapprove of these types of economic offences. We have disapproval of other types of social offences. That kind of social disapproval for economic offences is needed to arrive at a permanent solution, an ultimate solution, of the menace which is being created by the generation and operation of black money.

Mr. Vice-Chairman, Sir, while making their observations, certain hon. Members wanted to know what steps we are going to take, so far as the simplification of procedures and other types of measures which may be broadly termed as rationalization of the tax system, $ar_e$ concerned. You will appreciate and I hope $th_e$ hon. House will appreciate that it is, a pre-budget session and it would not be possible for me to dwell on that subject in detail. But what I can tell the hon. Members is that this is also an exercise which is made continuously. We are trying to improve our tax system. We are trying to improve our machinery. $Variou_s$ amendments are being brought forward. I cannot rule out the possibility that, in that process, sometimes it becomes more complex instead of becoming simplified. But, in a developing economy like ours where this instrument is being utilis-

ed not merely for releasing certain revenues, but, at the same time; also for doing away with the economic disparities which are prevailing in the various strata of the society on the one hand and for creating an atmosphere of savings and investments on the other hand, sometimes complexity of the law becomes unavoidable. At the same time, I can assure the hon. Members that so far as simplifications is concerned and the procedural matter is concerned, we are alive to the problem. We are trying $t_0$ sort it out and to make it simpler as far as possible. A constant exercise will be made in that direction.

While making his observations, Mr. O. P. Tyagi, rather critically, suggested that the policies of the Government are responsible for the generation of black money. Sir, I would most respectfully beg to differ from his observations. It is not the policies of the Governments. Partly, we can say that the socio-economic conditions in which we are living today are responsible. As the figures which I have indicated would clearly show, neither the lower income group nor the working class people or the common people are committing these types of economic offences. The elites are committing these types of economic offences. Either they are doing it themselves or they are helping it. The criterion of successful lawyer depends on how much money Tie earns. Whether he earns the money by clearing income-tax. cases or by showing his legal excellence otherwise is not being taken into consideration. In a system like this, whatever legislative and administrative measures we may have, it would not be possible for us to rule out the possibility of generation of block money through tax evasion or tax avoidance.

He has suggested that perhaps all those people who resorted to take advantage of the voluntary disclosure schemes on earlier occasions have come forward and taken advantage of the present scheme. Perhaps, it would be too much to come to that conclusion. I have some figures with me about the earlier disclosures. In 1951, the total number of disclosures was only 20,912. There were two schemes in 1965—60:40 Scheme and the Block Scheme—and the total number of disclosures under these two schemes taken together was 1,16,000 and odd. This time, the number is 2,58,000. Therefore, even if we come to the conclusion that all those who availed of the opportunity on the earlier occasions have taken the opportunity for this disclosure also, there is a big gap and some new people have joined. Sir, he wanted to know what type of people and particularly what income group of people $hav_e$ taken advantage of this opportunity. It would $^{no}$t be possible for me. As I have already indicated 2,58,000 assessees have made declarations. It was done in different parts of the country and the computation is still going on. Even there is a difference in the figure which I gave in Lok Sabha and the figure I have given here today because from various parts the information is still coming. Therefore, it will take quite a good deal of time to arrive at the actual figure and to identify as to how many assessees from which income level made the declarations.

Sir, Mr. Yogendra Sharma made the observation and Mr. Anandam corroborated it to some extent that most of the raids which we are conducting are infructuous. I would like to submit most respectfully, Sir, the picture is otherwise. Most of the raids have been successful. There may be one or two raids where there has not been sufficient material, but most of the raids conducted by the Income-tax Department people today are successful. We are in a position to seize not only assets but also valuable documents which indicate tax evasion to a considerable extent. In that connection, Sir, Mr. Anandam suggested: Why are $w_e$ not penalising $th_e$ infor-

[Shri Pranab Mukherjee]

mers if they give any wrong information? There too, Sir, there is an element of risk. There are certain provisions that informers are to give certain particulars. But if we want to make it a point to penalise him if his information is wrong, then nobody would come forward to give information, and it would not be possible for the Department to build up the intelligence wing to such an extent that they will get and collect all sorts of information of tax evasion and tax avoidance. There is no denial of the fact that on the basis of the information we are getting from various informers, quite a number of successful raids have been conducted. It is to be kept in mind that here the tax evaders and tax avoiders are not ordinary type of p*eople. They have a control over the society. They are respectable men in the society because of the power of their money bags. Therefore, when the informers come to leak some information, they take some amount of risk, and that amount of risk is there. I think, it would not be wise to add to that risk and to bring them to a more disadvantageous position. But at the same time, Sir, the Department makes some scrutiny, they make some examination before they initiate the raids and searches on the basis of the information available to them.

Sir, while making her observations, Smt. Sumitra Gandhi Kulkami suggested as to what we are going to do about th$_e$ Income-tax Depv+ment. I am really glad that she has appreciated the stand taken by the Department. This is the Department which was criticized many a time on the floor of the House. But at the same time, Sir, perhaps, you will agree with me, and the hon. House will agree with me, but for their untiring efforts and seriousness, it would not have been possible to bring this much amount of money to the mainstream of our national economy. So far as the problems of promotion and improvement of their working conditions are concerned, these matters are receiving the constant attention of the Department. But at the same time we cannot sort out these problems because these have ramifications in other areas also. Whatever is possible for us to do within the limited power of the Department, we have done it. Regarding other matters, there are certain actions and reactions in various other similar type of services. We shall have to keep that in mind. But I appreciate the good gesture she has shown to the Department.

Sir, I think, the major points which the hon. Members mentioned have already been covered by me. Again I express my^gratitude to all the hon. Members for giving snpport to this Bill and I hope that thi$_s$ Bill will receive the unanimous support of the House.

SHRIMATI SUMITRA G. KUL-KARNI: I suggested that only $_a$ segment of the industry should be taken up for a concentrated effort and also only 10 per cent of the cases should be taken up rather than taking up all the cases. It is only a departmental administrative suggestion.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): I shall first put the Resolution to vote. The question is:

> "That this House disapproves the Voluntary Disclosure of Income and Wealth Ordinance, 1975 (No. 15 of 1975) promulgated by the President on the 8th October, 1975."

*The motion was negatived.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): I shall now put the motion to vote. The question *is:*

> "That the Bill to provide for voluntary disclosure of income and wealth and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by th$_e$ Lok Sabha, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 7 *were* added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU; Clause 8. There is one amendment by Dr. K. Mathew Kurian and Shri Viswanatha Menon. Both of them are not here.

Clause 8 *was added to the Bill.*

*Clauses* 9 to 22 and *the Schedule were added to the Bill,*

*Clause* 1, *the Enacting Formula and the* Title *were* added to the Bill.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

"That the Bill be returned."

*The question was put and the motion was* adopted.

## SMUGGLERS AND FOREIGN EXCHANGE MANIPULATORS (FORFEITURE OF PROPERTY) BILL, 1976

THE MINISTER OF STATE IN-•CHARGE OF THE DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for the forfeiture of illegally acquired properties of smugglers and foreign exchange munipulators and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, this short Bill seeks to replace, with some minor modifications, the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Ordinance, 1975.

The Bill provides for the forfeiture of illegally acquired properties of smugglers and foreign exchange manipulators in order to effectively curb their anti-social activities. The provisions of the Bill will apply to persons convicted under the customs or foreign exchange laws and those in respect of whom orders of detention under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 have been made. They will also cover the relatives, associates and confidants of such persons. In order to ensure that small one-time offenders under the customs and foreign exchange laws are not deprived of their properties, the Bill will be applicable only in the case of persons who have been convicted of offences under these laws involving an amount exceeding rupees one lakh or those who have been convicted thereunder more than once. The Bill

makes it unlawful for the per-4 P.M. sons falling in the aforesaid

categories to hold any 'illegally acquired property', either by themselves or through any other persons on their behalf. The expression 'illegally acquired property' has been defined to include any property which is acquired out of income, earnings or assets obtained from any activity prohibited by any law relating to any matter within the legislative competence of Parliament or out of income, earnings or assets in respect of which any such law has been contravened. It will also include property acquired out of any income, earnings or assets the source of which cannot be proved. If a person holds any property which would have been 'illegally acquired property' in relation to a previous holder, it would also be given the same treatment in his hands unless it has been subjected to a transfer in good faith for adequate consideration.

The provisions of the Bill will be administered by senior officers of the Central Government not below the rank of Joint Secretary to the Govern-